राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई,उतरप्रदेश,बिहार,राजस्थान,मध्यप्रदेश,उतरांचल,उतराखंड,दिल्ली,हरियाणा में प्रसारीत

क्रांति समय
SURESH MAURYA
(Chief Editor)
M. 98791 41480
Working. off.: STPI-SURAT, GUJARAT-395023
(Software Technology Park of India, Surat.
www.krantisamay.com
www.krantisamay.in
krantisamay@gmail.com

सुरत–गुजरात,संस्करण शनिवार,19सितम्बर2020 वर्ष–3, अंक –233 पृष्ठ–08 मूल्य–01रुपये

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

भारत से गई रेल का नेपाल में जबरदस्त स्वागत, देखने के लिए उमड़ी हजारों की भीड़

नई दिल्ली।

भारत सरकार के सहयोग से जब नेपाल में पहली रेल पहुंची तो जनकपुर स्टेशन पर लोगों का उत्साह देखते ही बना। हजारों की संख्या में लोग स्टेशन और आसपास के इलाके में घंटों से खड़े रहकर रेल का भव्य स्वागत किया। रेल के स्टेशन पर आते ही लोगों ने ताली और सीटी बजाकर स्वागत किया। हर कोई इस रेल के साथ सेल्फी लेता हुआ दिख रहा था। नेपाल के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। भारत के सहयोग से आम नेपाली जनता का अपनी भूमि पर रेल चलने का सपना साकार हुआ। चीन नेपाल में रेल लाने की बात कह कर ठगता रहा है और भारत ने नेपाल में रेल की पटरी बिछाकर उस पर रेल चलाकर नेपाली जनता के वर्षों पुराने सपने को साकार कर दिया। इसके साथ ही अब नेपाल की सरजमीं पर रेल सेवा भी उपलब्ध हो गई है। नेपाल भारत के बीच यह पहली रेल सेवा की शुरुआत हो गई है। जल्द ही अन्य सीमाओं से भी नेपाल तक रेल चलने की उम्मीद है क्योंकि उसका निर्माण कार्य जारी है। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से काठमांडू को रेल लाइन से जोड़ने का वादा किया है और इसके लिए रक्सौल से काठमांडू तक के रेल निर्माण का प्रारम्भिक कार्य भी पूरा किया जा चुका है। जल्द ही दोनों देशों के बीच एक समझौता होने के बाद इस काम की शुरुआत हो जाएगी। नेपाल और भारत के बीच में एक बार फिर से रेल सेवा की शुरुआत होने जा रही है। भारत सरकार के सहयोग से बना रेलवे लिंक बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुरधाम तक चलने वाला है। बाद में इसे नेपाल के अन्य शहरों तक विस्तार किये जाने की योजना है। हालांकि यह रेल लाइन पिछले साल ही बन कर तैयार हो गया था लेकिन 9 महीनों तक दोनों देशों के बीच में राजनीतिक और कुटनीतिक संबंधों में एक ठहराव आ जाने के कारण इसमें देरी हुई। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से भी इस रेल को नेपाल तक पहुचने में देरी हुई है, लेकिन अब जबकि दोनों देशों के बीच का कुटनीतिक संबंध जैसे ही पटरी पर आती दिख रही है।

दिल्ली में 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, केजरीवाल सरकार ने जारी किया आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली में सभी स्कूल 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार ने इस बारे में आदेश जारी किया है। दिल्ली सरकरा के इस आदेश का मतलब यह है कि 21 सितंबर से जो 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए आंशिक रूस से स्कूल खोलने की बात कही थी, वह भी रद्द कर दी गई है। अब केवल ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगी। कोरोना वायरस महामारी के चलते दिल्ली में मार्च से स्कूल बंद हैं। इससे पहले दिल्ली सरकार ने 5 सितंबर को दिल्ली में 30 सितंबर तक सभी स्कूलें बंद रखे जाने का आदेश जारी किया था। आदेश में कहा गया था कि ऑनलाइन पढ़ाई पहले की तरह ही जारी रहेगी। आदेश में कहा गया था कि 20 सितंबर तक छात्रों को किसी भी तरह की एक्टिविटी के लिए स्कूल ना बुलाया जाए। सरकार ने कहा था कि 21 सितंबर से अगर 9वीं से 12वीं क्लास के छात्र अपने स्कूल जाना चाहें और टीचर की सलाह लेना चाहें तो वे अपने पेरेंट की लिखित सहमति के साथ जा सकते हैं। हालांकि अगर स्कूल और छात्र का घर कन्टेनमेंट जोन में नहीं है तो ही इजाजत होगी। लेकिन यह स्वैच्छिक होगा। हालांकि अगर स्कूल और छात्र का घर कन्टेनमेंट जोन में नहीं है तो ही इजाजत होगी। लेकिन यह स्वैच्छिक होगा।

गांधी परिवार का नाम आने पर अनुराग ठाकुर पर भड़का विपक्ष, तीसरी बार लोकसभा हुई स्थगित

नेशनल डेस्क।

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान पर विपक्षी दलों की आपत्ति के कारण गुरुवार को लोक सभा की कार्यवाही तीन बार स्थगित की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से लोक सभा में कराधान और अन्य विधियां (कतिपय उपबंधों का संशोधन और छूट) विधेयक 2020 को पेश किया गया। इस विधेयक के प्रावधानों और पीएम केयर्स फंड पर विपक्ष की आपत्तियों पर जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम केयर्स फंड का विरोध सिफ इसलिए हो रहा है कि क्योंकि विपक्ष को हर चीज़ में खामी नज़र आती है। उन्होंने कहा कि वे लोग ईवीएम का विरोध करते हैं क्योंकि कई चुनाव हार गए हैं। ठाकुर ने कहा कि विपक्ष ने जन-धन योजना, नोटबंदी, तीन तलाक और जीएसटी जैसे फैसलों का भी विरोध किया था जो दर्शाता है कि इन फैसलों में नहीं बल्कि विपक्ष की नीयत में खोट है। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड में बच्चों से लेकर बुजुर्ग, अभिनेताओं, नेताओं और समाज के तमाम वर्गों ने दान दिया है। ऐसे में इस पर सवाल उठाना गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में गांधी-नेहरू परिवार के सदस्यों को निजी लाभ पहुचाने के लिए कई संस्थाएं बनाई गईं। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने 1948 में एक शाही आदेश की तरह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष बनाया लेकिन उसका पंजीकरण आज तक नहीं हो पाया। पंडित नेहरू और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इसके सदस्य रहे, इस पर बहस होनी चाहिए। चौधरी ने कहा कि गांधी-नेहरू परिवार पर लगाए गए ठाकुर के आरोप अनुचित है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का नाम लेकर उन पर आरोप लगाना अशोभनीय है।

जया बच्चन के 'थाली' वाले बयान पर भड़के शक्तिमान बोले- इंडस्ट्री किसी के बाप की नहीं है

नेशनल डेस्क। फिल्म जगत में ड्रग्स मामले को लेकर कई स्टार ही आमने-सामने आ गए हैं और एक-दसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सदस्य और अभिनेत्री जया बच्चन के राज्यसभा में दिए बयान के बाद टीवी के शक्तिमान और महाभारत के भीष्म पितामाह यानी मुकेश खन्ना ने उनके बयान पर नाराजगी जाहिर की है। मुकेश खन्ना ने कहा, 'सिर्फ इसलिए कि इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, आप वहां कमियां नहीं गिनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। और यहां हमें किसी ने खाना नहीं दिया हमने इसके लिए मेहनत की है'। जया बच्चन के बयान का विरोध करते हुए उन्होंने कहा दो टूक कहा कि उन्होंने किसी को थाली में खाना नहीं परोसा है। इंडस्ट्री किसी के बाप की नहीं है, यहां काम करने वाला हर शख्स मेहनत करता है। मुकेश खन्ना ने कहा कि इंडस्ट्री सालों से चली आ रही है। अब इसमें नेपोटिज्म बढ़ गया है, ग्रुपिज्म बढ़ गया है । इस पर अगर रवि किशन ड्रग का मामला उठाते हैं और आप (जया बच्चन) पलटकर ये कहती हैं, 'जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो। ये बयान हास्यास्पद है। उनका कहना है कि नियम तोड़ने वालों पर जनता की नजर है। कोई इंडस्ट्री को गटर नहीं बता रहा, सिर्फ जांच की मांग हो रही है। इसलिए जया बच चन को शोर मचाने की बजाय शांत बैठना चाहिए और जांच के निर्देश का इंतजार करना चाहिए। इससे पहले जया बच्चन के राज्यसभा में दिए बयान के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत ने ट्वीट कर उन पर नाशाना साधा था। कंगना रनौत ने ट्वीट किया था कि जया जी अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती क्या तब भी आप यही कहतीं। कंगना ने पूछा कि अगर श्वेता नशे और छेड़छाड़ के खिलाफ बोलती क्या तब भी जया का यही जवाब होता। अगर अभिषेक लगातार बदमाशी और उत्पीड़न का शिकार होता है और एक दिन फंदे पर झूलता मिलता तब भी क्या जया जी आप यही सब बोलतीं। कंगना ने लिखा जया जी हमारे लिए भी अपना कुछ कर्त्तव्य निभाओ। बता दें कि राज्यसभा में जया बच्चन ने रवि किशन पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में किसी भी संकट के दौरान सहायता में कभी पीछे नहीं रहने वाला यह उद्योग सराहना का हकदार है। उन्होंने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि दुख की बात यह है कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं, उसी थाली में छेद करते हैं। जया ने कहा कि केवल कुछ लोगों की वजह से आज मनोरंजन उद्योग आलोचना का शिकार हो रहा है ।

संक्षिप्त समाचार

जयाप्रदा का जया बच्चन पर फूटा गुस्सा, बोलीं- तब क्यों चुप थीं जब आजम ने मेरे लिए बोले अपशब्द

नई दिल्ली। बॉलीवुड से जुड़े सभी विवादों का असर अब राजनीति पर पड़ने लगा है। हाल ही में सांसद रवि किशन ने लोकसभा में बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर हो रहे विवाद को खत्म करने का मुद्दा उठाया। इस पर जया बच्चन ने राज्यसभा में पलटवार करते हुए रवि किशन पर बॉलीवुड को बदनाम करने का आरोप लगाया। जिस पर घमासन मच गया है। ऐसे में बीजेपी नेत्री जयाप्रदा भी इस लड़ाई में कूद पड़ी है। जयाप्रदा ने कहा जब आजम खान ने उन पर विवादित टिप्पणी की थी, उस समय वह चुप क्यों थीं। जया प्रदा ने कहा, जया बच्चन ड्रग्स मामले पर खुलकर बोल रही हैं, लेकिन जब 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मेरे ऊपर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया था तब वो खामोश थी। उन्होंने कहा, उस वक्त कई लोगों ने मेरा समर्थन किया, लेकिन जया बच्चन ने इसका विरोध नहीं किया। एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए जया प्रदा ने कहा कि किसी मुद्दे पर खुलकर बोलना और किसी पर बिल्कुल शांत रहना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स मामले पर जया बच्चन ने खुलकर बात की, लेकिन कंगना रनौत के समर्थन में उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। जया प्रदा ने कहा, कंगना रनौत के खिलाफ राजनीति हुई, लेकिन जया बच्चन खामोश रहीं, उन्हें कुछ बोलना चाहिए था। जया प्रदा ने कहा, बॉलीवुड इंडस्ट्री को कोई भी बदनाम नहीं कर सकता है। रवि किशन ने जो कुछ कहा जया बच्चन अपने ऊपर ले गईं। उन्होंने कहा कि जया बच्चन ने जो कहा वो अपनी पार्टी से प्रभावित होकर कहा।

पाकिस्तान जेल से रिहा हुआ युवक पहुंचा घर, गायब हुए बेटे को मृत समझ बैठे थे परिजन अब...

रीवा। पाकिस्तान की लाहौर जेल से रिहा हुआ मध्य प्रदेश का अनिल साकेत आज 5 साल बाद अपने घर पहुंचा। ग्वालियर होते हुए सड़क मार्ग से रीवा पहुंचे अनिल साकेत का जगह-जगह स्वागत किया गया। उसके इंतजार में पूरा गांव व परिवार पलके बिछाकर बैठा था। बता दें कि अनिल वर्ष 2015 में गायब हो गया था। पिछले वर्ष 2019 में उसके पाकिस्तान के लाहौर जेल में बंद होने की खबर आई थी जिसके बाद अब पाकिस्तान सरकार ने लाहौर जेल में बंद 320 कैदियों की रिहाई की जिसमें रीवा के अनिल कुशवाहा भी रिहा हुए। वे 14 सितंबर को बाघा बार्डर पहुंचे थे। जहां से आज उन्हें जांच के बाद रीवा लाया गया है। युवक की घर वापसी के बाद से ही स्थानीय लोगों में खुशी की लहर छाई हुई थी। जिला मुख्यालय से लगभग 80 किमी दूर नईगढ़ी तहसील के छदहाई गांव निवासी अनिल साकेत 3 जनवरी 2015 को अचानक घर से लापता हो गया था। परिजनों ने तब नईगढ़ी थाने में 10 जनवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। कई बार थाने गए, पुलिस से ढूंढने को कहा लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। ऐसे करके पूरे साढ़े चार साल गुजर गए और परिजनों ने उसके लौटने की आस छोड़ दी। लेकिन जून 2019 में भारत सरकार के विदेश विभाग के द्वारा नईगढ़ी थाने में एक पत्र भेजा गया जिसमें पिछले 3 साल से लाहौर जेल में बंद कैदी अनिल साकेत के बारे में जानकारी मांगी गई।

मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा- विरोध करने वाले दे रहे बिचौलियों का साथ

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के किसानों को आश्वस्त किया कि लोकसभा से पारित कृषि सुधार संबंधी विधेयक उनके लिए रक्षा कवच का काम करेंगे और नए प्रावधान लागू होने के कारण वे अपनी फसल को देश के किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेंगे। प्रधानमंत्री ने विपक्षी पार्टियों, खासकर कांग्रेस पर, आरोप लगाया कि वह इन विधेयकों का विरोध कर किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही हैं और बिचौलियों के साथ किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रही हैं। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे इस भ्रम में न पड़ें और सतर्क रहें। मोदी ने ये बातें आज 'ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु को राष्ट्र को समर्पित करने और बिहार के रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिए 12 रेल परियोजनाओं का शुभारंभ करने के बाद अपने संबोधन में कही। वीडियो कांफ्रेंस से आयोजित इस समारोह में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, ''कल विश्वकर्मा जयंती के दिन लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए ये विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर आए हैं। मोदी ने कहा कि जो लोग दशकों तक सत्ता में रहे हैं और देश पर राज किया है, वे लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं ओर उनसे झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, ''जिस एपीएमसी एक्ट को लेकर अब ये लोग राजनीति कर रहे हैं, एग्रीकल्चर मार्केट के प्रावधानों में बदलाव का विरोध कर रहे हैं, उसी बदलाव की बात इन लोगों ने अपने घोषणापत्र में भी लिखी थी। लेकिन अब जब एनडीए सरकार ने ये बदलाव कर दिया है, तो ये लोग इसका विरोध करने पर उतर आए हैं। दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान-गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों को धोखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी, कोई भी व्यक्ति अपना उत्पाद दुनिया में कहीं भी बेच सकता है। जहां चाहे वहां बेच सकता है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए जितना राजग शासन में पिछले छह वर्षों में किया गया है, उतना पहले कभी नहीं किया गया। उन्होंने कहा, ''मैं आज देश के किसानों को बड़ी नम्रता पूर्वक अपनी बात बताना चाहता हूं। संदेश देना चाहता हूं। आप किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए। इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है ऐसे लोगों से सावधान रहें, जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और जो आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं। वे लोग किसानों की रक्षा का ढिंढोरा पीट रहे हैं। मोदी ने कहा कि इन

विधेयकों का विरोध करने वाले किसानों को अनेक बंधनों में जकड़ कर रखना चाहते हैं। ''वे लोग बिचौलियों का साथ दे रहे हैं...किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को अपनी उपज कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना बहुत ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा, ''21वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं रहेगा। भारत का किसान खुलकर खेती करेगा। जहां मन होगा, अपनी उपज बेचेगा। जहां ज्यादा पैसा मिलेगा, वहां बेचेगा।

किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं रहेगा। यह देश की जरूरत है और समय की मांग भी है। लोकसभा ने बृहस्पतिवार को कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक पारित कर दिया था।

कश्मीर में लाभकारी योजनाओं को सौ प्रतिशत सुनिश्चित करना ही जन अभियान का उद्देश्य

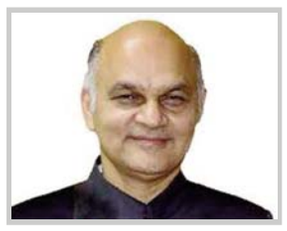

श्रीनगर। उप राज्यपाल के सलाहकार के के शर्मा ने कहा कि जन अभियान का उद्देश्य कम समय में जनता की समस्याओं को हल करना और सेवाओं को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि जन लाभ वाली योजनाओं को तय समय में लोगों तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। उन्होंने ब्लाक दिवस के तहत गांदरबल का दौरा किया। शर्मा ने पीआरआई के तहत लोगों की भागीदारी देखी और पंचायत के सदस्यों के द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना की। इस मौके पर जन समस्याओं को सुनने के लिए सभी ब्लाक के अधिकारी मौजूद थे। विभागों ने स्टाल लगा रखे थे जिनमें लोगों को विभाग के कार्यों के बारे में जानकारी दी जा रही थीं। शर्मा ने श्रम सहायता स्कीम के तहत चैक भी बांटे। वहीं थ्रेशर, पासबुक आदि भी लोगों को दी गई। के के शर्मा ने कहा कि बैक टू विलेज कार्यक्रम लोगों तक पहुंच बनाने का जरिया है। इसका मकसद डोर टू डोर जाकर लोगों की समस्याओं को सुनना है।अधिकारी दो से तीन दिन पंचायत में रहते हैं और विकास से जुड़ी लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। और उसी के तहत योजनाएं तैयार होती हैं। उन्होंने कहा, उद्देश्य है विकास करना न कि विकास की बात करना। अधिकारी दो से तीन दिन पंचायत में रहते हैं और विकास से जुड़ी लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। और उसी के तहत योजनाएं तैयार होती हैं। उन्होंने कहा, उद्देश्य है विकास करना न कि विकास की बात करना।

सरकार से उठ चुका है किसानों का विश्वास, मोदी किसान विरोधी: राहुल गांधी

नई दिल्ली।

कांग्रेस ने लोकसभा में पारित हुए कृषि संबंधी विधेयकों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विपक्षी दलों पर निशाना साधे जाने के बाद शुक्रवार को आरोप लगाया कि इस सरकार से किसानों का विश्वास उठ चुका है तथा वह देश के किसान एवं मजदूरों को बरगला रही है। पार्टी ने यह भी कहा कि इस कुरुक्षेत्र में सरकार कौरव है और किसान-मजदूर पांडव हैं तथा कांग्रेस, पांडवों के साथ खड़ी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, किसान का मोदी सरकार से विश्वास उठ चुका है क्योंकि शुरू से मोदी जी की कथनी और करनी में फर्क रहा है। नोटबंदी,गलत जीएसटी और डीजल पर भारी कर। जागृत किसान जानता है- कृषि विधेयक से मोदी सरकार बढ़ाएगी अपने मित्रों का व्यापार और करेगी किसान की रोज़ी-रोटी पर वार। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को देश के किसानों को आश्वस्त किया कि लोकसभा से पारित कृषि सुधार संबंधी विधेयक उनके लिए रक्षा कवच का काम करेंगे और नए प्रावधान लागू होने के कारण वे अपनी फसल को देश के किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेंगे। प्रधानमंत्री ने विपक्षी पार्टियों, खासकर कांग्रेस पर, आरोप लगाया कि वह इन विधेयकों का विरोध कर किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही हैं और दावा किया कि इन विधेयकों के कानून बनने के बाद 21वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं रहेगा। उन्होंने इन विधेयकों को देश की जरूरत और समय की मांग बताया। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम में न पड़ें और सतर्क रहें। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया, प्रधानमंत्री के उच्च पद पर बैठे व्यक्ति को देश को बरगलाने से परहेज करना चाहिए। ऐसा करना अशोभनीय है। दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। वह किसान विरोधी हैं और खेती पर अतिक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया, प्रधानमंत्री ने बार बार यह कहा कि ये तीनों विधेयक किसान के पक्षधर हैं। हम पूछना चाहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खत्म करने की साजिश क्यों की जा रही है? न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे देंगे और कहां देंगे क्योंकि मंडिया तो खत्म हो जाएंगी? एमएसपी कौन देगा और किसको देगा? उन्होंने सवाल किया, प्रधानमंत्री ने बार बार यह कहा कि ये तीनों विधेयक किसान के पक्षधर

हैं। हम पूछना चाहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खत्म करने की साजिश क्यों की जा रही है? न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे देंगे और कहां देंगे क्योंकि मंडिया तो खत्म हो जाएंगी? एमएसपी कौन देगा और किसको देगा? सुरजेवाला ने यह भी पूछा, क्या एमएसपी देने के लिए एफसीआई 62 करोड़ किसानों के खेत में जाएगी? देश में 60 फीसदी दो एकड़ से कम के मालिक हैं। वे क्या करेंगे? वो मध्य प्रदेश से मद्रास और मद्रास से कोलकाता जाकर कैसे अपनी फसल बेचेंगे? कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने सवाल किया, किसान बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने कैसे खड़ा हो पाएगा? अगर आप मंडी खत्म करेंगे तो 62 करोड़ किसान-खेत मजदूर सामूहिक संगठन बनाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे निर्धारण करेंगे? प्रांतों की आय मार्केट फीस से होती है जिससे गांवों का विकास होता है। इसका क्या होगा? उन्होंने कहा, इस कुरुक्षेत्र में सरकार कौरव है, पांडव देश का किसान-मजदूर है।

शोपियां 'फर्जी एनकाउंटर' में बड़ा खुलासा, सेना के जवानों ने किया 'अफस्पा' का दुरुपयोग

नेशनल डेस्क। शोपियां में मारे गए तीन लोगों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सेना को शुरूआती जांच में पता चला है कि जवानों ने अफस्पा के तहत मिली शक्तियों का दुरुपरयोग किया था। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि सेना को प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले हैं कि जवानों ने शोपियां फर्जी मुठभेड़ में अफस्पा के तहत मिली शक्तियों का उल्लंघन किया, जिसमें जुलाई में तीन लोग मारे गए थे। यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब कुछ परिवारों ने राजौरी जिले के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनके परिवार के तीन सदस्य शोपिया के अम्शीपोरा से 17 जुलाई से लापता हैं जहां पर वे सेब और अखरोट के बागान में बतौर मजदूर काम करते थे। परिवारों ने संयुक्त रूप से शिकायत दर्ज कराई और तस्वीर दी और बताया कि 21 वर्षीय मोहम्मद इबरार, 18 वर्षीय इबरार अहमद और 26 वर्षीय इम्तियाज अहमद लापता हैं जिसके बाद यह जानकारी मामले की जांच के लिए कश्मीर पुलिस को सौंप दी गई। उल्लेखनीय है कि शोपियां के अम्शीपोरा गांव में हुई मुठभेड़ की जांच सेना ने पहले ही शुरू कर दी है। सेना ने 18 जुलाई को दावा किया था कि दक्षिण कश्मीर के शोपियां में तीन आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन इसकी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। श्रीनगर में सेना के प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने सोमवार (10 अगस्त) को जारी बयान में कहा कि सेना ने 18 जुलाई 2020 को शोपियां में मुठभेड़ को लेकर सोशल मीडिया में चल रही बातों को संज्ञान में लिया है। श्रीनगर में सेना के प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने सोमवार (10 अगस्त) को जारी बयान में कहा कि सेना ने 18 जुलाई 2020 को शोपियां में मुठभेड़ को लेकर सोशल मीडिया में चल रही बातों को संज्ञान में लिया है। शोपियां में मुठभेड़ को लेकर सोशल मीडिया में चल रही बातों को संज्ञान में लिया है।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संपादकीय

जरूरी परिपक्वता

राज्यसभा में रक्षा मंत्री ने भारत का पक्ष जिस तरह से पेश किया, उसकी सराहना होनी चाहिए। पड़ोसी देश के प्रति जहां दृढ़ता का स्वर स्वाभाविक था, वहीं ऐसे समय में भी सुधार के प्रति संवेदना साफ तौर पर सामने आई। तानाशाह पड़ोसी की मनमानियों के बावजूद भारतीय रक्षा मंत्री का बयान देश के बड़प्पन को ही जाहिर करता है। जहां स्वयं न झुकने की बात हुई, वहीं यह भी कह दिया गया कि हम दूसरे का मस्तक भी नहीं झुकाना चाहते। किसी भी पड़ोसी देश की संप्रभुता का इससे ज्यादा सम्मान नहीं हो सकता। ऐसे समय में भी हम जिस स्तर की शालीनता, संयम और समझदारी का परिचय दे रहे हैं, दुनिया देख रही है। चीन का लहजा सामने कुछ होता है व पीठ पीछे कुछ और। वह वार्ता में सहमति बनाने की बात करता है, लेकिन जमीन पर उग्रता बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। चीन के पूरे संदर्भ में रक्षा मंत्री का बयान एक लोकतांत्रिक और संतुलित देश की ओर से दिया गया माकूल जवाब है। ऐसे बयान की उम्मीद शायद चीन को भी नहीं होगी। उसे खासतौर पर अपनी कथनी और करनी के अंतर को दूर करने के कोशिश जरूर करनी चाहिए। पूरी दुनिया चीन का व्यवहार देख रही है, वह अपनी हरकतों से कतई यह आभास नहीं कराता कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता वाला जिम्मेदार देश है। गुरुवार को राज्यसभा में रक्षा मंत्री का बयान जितना महत्वपूर्ण था, उससे कहीं ज्यादा जरूरी था राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू का सुझाव। भारत-चीन संदर्भ में कुछ नेता अतिरिक्त प्रश्न पूछना चाहते थे, इस पर उप-राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री से कहा कि वह प्रमुख नेताओं को अपने कक्ष में बुलाकर जानकारी दें। उप-राष्ट्रपति का यह परिपक्व रुख सराहनीय है। आजकल हर तरह के सवाल पूछने का चलन हो गया है, अनावश्यक रूप से परेशान करने वाले या देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले सवाल पूछने से भी कई लोगों को गुरेज नहीं रहा। ऐसे लोगों का संयम में रहना सबसे जरूरी है और इसके बावजूद अगर वे सवाल पूछना चाहते हैं, तो उप-राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से रास्ता बता दिया है। इस अवसर पर उप-राष्ट्रपति ने सांसदों को जिस ढंग से समझाया, कायदे से उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। उन्होंने याद दिलाया कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है और सेना सीमा पर खड़ी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुष्प्रचार चल रहा है कि भारत में इस मुद्दे पर मतभेद है। उप-राष्ट्रपति ने उचित ही कहा कि हमें इस सदन के माध्यम से ऐसा संदेश देना चाहिए कि पूरा देश और संसद सेना के साथ एकजुट है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की परंपरा और संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम और सर्वेजना सुखिना भवन्तु पर आधारित रही है। हजारों साल के इतिहास में हमने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया है। उप-राष्ट्रपति के ऐसे निवेदन भाषण से माहौल बदल गया। विपक्षी नेता भी देश की एकता और अखंडता की दुहाई देने लगे। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने तो यहां तक कह दिया कि 'उनकी पार्टी चीन के साथ विवाद सुलझाने के मुद्दे पर पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ी है।' राज्यसभा ने देश की राजनीतिक-विधाई एकजुटता का जो संदेश दिया है, उसी की रोशनी में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, तभी हम जल्द से जल्द किसी समाधान तक पहुंच पाएंगे।

चीन के खिलाफ वैश्विक एकजुटता का वक्त

जी. पार्थसारथी

किसी मुल्क की मजबूती और लचीलापन उसके नागरिकों द्वारा दिखाई जाने वाली हिम्मत और सहन शक्ति से निर्धारित होती है। भारत के नागरिकों ने सबसे मुश्किल चुनौतियों का सामना किया जब वर्ष 1918 में देश जानलेवा फ्लू की जद में आ गया था। उस महामारी में अनुमान के मुताबिक 1.4 से 1.7 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। अब कोई पूरे एक सौ साल बाद फिर से भारत को भी कोविड-19 की महामारी की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक इस बीमारी से विश्वभर में लगभग 2.9 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं और भारत में करीब 50 लाख केस हुए हैं। लेकिन इस बार इसमें सीमा पर चीनी घुसपैठ के रूप में एक और गंभीर समस्या भी आन जुड़ी है। चीन अपनी इलाकाई महत्वाकांक्षा को पूरा करने को अक्सर एशिया-प्रशांत के पड़ोसियों को डराने हेतु भुजाएं फड़फड़ाता रहता है। लेकिन जिस बात का चीन को अंदाज नहीं था वह है भारत सरकार और सेना एवं नागरिकों द्वारा दिखाई गई दृढ़ता, जो लद्दाख में चीन की इलाका कब्जाने संबंधी महत्वाकांक्षा को जी-जान लड़ा कर वापस धकेलने में देखने को मिली है। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग जी के बीच 10 सितंबर को मास्को में मुलाकात हुई है, जिसमें लद्दाख सीमा पर बने तनाव को फौरन घटाने के लिए वार्ता की गई है। इसमें मुख्य निर्णय यह हुआ कि दोनों पक्ष ऐसा कुछ करने से परहेज रखेंगे, जिससे तनाव में और इजाफा हो, पिछली बैठकों में किए गए समझौते और प्रतिबद्धता पर कायम रहेंगे ताकि सीमा पर शांति बनी रहे। इस बैठक में क्रियान्वयन योग्य जिस हिस्से पर सहमति बनी है वह यह कि लद्दाख में भारत-चीन के सैन्य कमांडरों के बीच जल्द ही बैठक होगी ताकि दोनों पक्ष संवाद के जरिए सीमा रेखा से अपने सैनिक पीछे हटाने हेतु रास्ता निकाल सकें। जब से चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षा को भारत ने अपने प्रतिकर्म से पैंगोंग झील में डुबो डाला है तब से चीन की नाटकबाजियां ज्यादा उग्र हो गई हैं। इस क्षेत्र की ऊंची चोटियों पर अपना नियंत्रण बनाने के बाद भारतीय सेना ने खुद को ऐसे सामरिक बिंदुओं पर सुदृढ़ कर लिया है, जिससे चीनी फौज के और आगे बढ़ने के प्रयासों में रुकावटें खड़ी हो गई हैं, जबकि उसका इरादा देपसांग क्षेत्र और सामरिक महत्व के दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी तक भारतीय पहुंच को चुनौती देना था। भारतीय सैनिक अब इस इलाके में पहले की तरह बेरोकटोक आवाजाही कर सकते हैं। भारत लद्दाख में दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच वार्ता का हिमायती है ताकि तनाव खत्म किया जा सके। हालांकि, चीन के सामने अपनी तरफ का प्रबंधन करने को पहले काफी गंभीर समस्याओं से निपटना होगा, जिन इलाकों पर उसने नियंत्रण बनाया है वह जल्द ही आगामी सर्दी की बर्फ में दब जाएंगे, जो कि अक्तूबर के महीने में गिरनी शुरू जाती है। भारतीय समकक्षों की बनिस्बत जो सर्दी भर सियाचिन में तैनात रहते हैं चीनियों को ऐसा कोई वास्तविक युद्धक अनुभव नहीं है। इधर, लद्दाख में जो इलाका भारत के नियंत्रण में है अब वहां से सर्दी में भी अपने सैनिक पीछे हटाने के कोई सवाल तब तक नहीं है जब तक कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा की सटीक शिनाख्त करवाने के लिए नक्शा पेश नहीं कर देता। साथ ही सीमा संबंधी विवाद को सुलझाने के लिए संजीदा होकर बातचीत में आगे नहीं बढ़ता। वर्ष 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वेन जिया बाओ ने 'भारत-चीन सीमा विवाद निदान हेतु राजनीतिक पैमाने एवं मार्गदर्शक सिद्धांत' नामक संधि को सिरे चढ़ाया था। समझौते में कहा गया था कि दोनों पक्ष सीमा की सुस्पष्ट निशानदेही के लिए आसानी से पहचाने जा सकने वाले प्राकृतिक भौगोलिक चिन्हों को दर्ज करते हुए सीमा नियंत्रण रेखा का निर्धारण करेंगे। साथ ही सीमा संबंधी निपटारा करते वक्त दोनों पक्ष सीमांत इलाकों में रह रहे अपने नागरिकों के हितों का भी ध्यान रखेंगे। परंतु बाद में चीन ने सीमा संबंधी निशानदेही करने के लिए सटीक लोकेशन देने से इनकार किया था, हालांकि दावा यह कि वह संधि का सम्मान करता है। चीन वास्तविक सीमा रेखा को लेकर जान-बूझकर असमंजस बनाए रखना चाहता है ताकि जब चाहे इलाकों पर मनमाफिक दावे कर सके। हालांकि, इनकी सत्यापना के लिए उसके पास ठोस ऐतिहासिक आधार या प्रमाण नहीं है। निःसंदेह चीन के दंभपूर्ण व्यवहार और उद्दंडता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की चिंताएं बढ़ रही हैं। चीन स्थापित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों को धता बताकर दक्षिण चीन सागर के पड़ोसी मुल्कों जैसे कि फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई के सागरीय इलाकों पर अपना दावा करते हुए कुछ द्वीपों पर कब्जा कर भी चुका है। जापान और ताईवान के साथ भी उसने सीमा संबंधी आक्रामक तेवर अपना रखे हैं। चीन को वर्ष 1979 में वियतनाम के साथ हुए युद्ध में मुंह की खानी पड़ी थी और जाहिर है यह बेइज्जती भरी हार आज भी उसके ज़ेहन में है। आसियान संगठन के 10 देशों ने अब आपस में हाथ मिलाते हुए मांग की है कि चीन को संयुक्त राष्ट्र समुद्र-कानून संहिता का पालन करना चाहिए, इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्र कानून न्यायाधिकरण ने भी चीन को स्थापित नियमों का उल्लंघन करने का दोषी करार दिया था। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के लिए मौजूदा समय बहुत मुश्किल है क्योंकि हाल ही में जिन यूरोपियन देशों की यात्रा पर गए, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, इटली और चेक गणराज्य शामिल हैं, वहां-वहां मेजबानों ने चीन के शिनजियांग प्रांत और हांगकांग में मानवीय अधिकार मूल्यों के हनन के अलावा उसकी 5-जी महत्वाकांक्षा को लेकर चिंताएं जताई हैं। भारत के साथ रिश्तों में चीन का मुख्य ध्यान सीमा के पुनः निर्धारण पर है, जबकि ठीक इसी वक्त वह क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रभाव को घटाना चाहता है। साथ ही वह भारत की मुक्त और नियम-आधारित व्यापार एवं निवेश नीतियों का भी दोहन करना चाहता है। एशिया और अफ्रीका भर में विकासशील मुल्कों को अब पता चल गया है कि मदद के नाम पर दिए गए चालाक शर्तों वाले चीनी कर्ज को उतारने में वे असमर्थ हैं। इसलिए अब बाध्य होकर अपने प्राकृतिक खनिज स्रोत, बिजली उत्पादन क्षमताएं, बंदरगाह और हवाई अड्डे चीन को व्यापारिक एवं सैन्य गतिविधियों के लिए सौंपने पड़ेंगे। चीन का 'जमूरा' बनने को नया-नया उद्धृत हुआ नेपाल और इसके प्रधानमंत्री ओली जल्द ही उपरोक्त वर्णित मुल्कों की जमात में शामिल होने को मजबूर हो जाएंगे, जिनका चीन की तथाकथित सहायता से मोहभंग हो चुका है। चीन की बहुप्रचारित 'एक पट्टी-एक सड़क परियोजना', जिसका हिस्सा 'चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा' है, वह अब कहावत वाला सफेद हाथी बनता जा रहा है। इसके बावजूद चीन पाकिस्तान को सैन्य-आर्थिक-कूटनीतिक रूप में मदद देने की अपनी नीति पर कायम रहेगा। चीनी चुनौतियों के मुकाबले के अलावा भारत के पास और कोई विकल्प है भी नहीं।

चीन की दबंगई और विस्तारवादी महत्वाकांक्षा से निपटने को भारत की रणनीति का एक मुख्य उपाय 'क्वाथ' नामक चौकड़ी का गठन किया जाना है। इस गठजोड़ में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका हैं। इसका संज्ञान लेकर चीन ने पहले ही चिंता और बौखलाहट के संकेत दिखा दिए हैं। क्वाड को अपनी सागरीय सुरक्षा गतिविधियों में वियतनाम और इंडोनेशिया को अपने साथ जोड़ना चाहिए। फ्रांस के साथ निकट सहयोग बनाते हुए क्वाड अपने संगठन को यूरोपीय आयाम दे सकता है। लेखक पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं।

आज के ट्वीट

आधे से ज़्यादा 'बॉलीवुड' वाले बहुत परेशान हैं, उनकी पहली परेशानी तो ये है कि उनका नशा उतर रहा है और दूसरी परेशानी ये कि उन्हें ये भी नहीं पता कि अब नशा मिलेगा कहाँ से

– अर्णव गोस्वामी

ज्ञान गंगा

मशीन

जग्गी वासुदेव

अगर आपको याद हो, जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा, तो आपके अंदर आजादी का एक जबरदस्त नया स्तर था। साइकिल सबसे बुनियादी मशीनों में से एक है, लेकिन जब आपने पहली बार चलाई, तो गतिशीलता के अगले स्तर पर जाने की आपकी क्षमता का यह अनुभव शानदार था। इंसान के धरती पर प्रबल स्थिति में होने का एकमात्र कारण है कि हमने औजार और मशीनें बनाई। आप एक तेंदुए जितना तेज नहीं दौड़ सकते। बाघ से नहीं लड़ सकते। आपकी हाथी से कोई बराबरी नहीं। आपकी बैल या गाय से भी बरबरी नहीं है। चूंकि हमने औजार और मशीनें बनाई, उससे हमारा जीवन उन्नत हुआ है। ये यंत्र ऐसी मशीनें हैं जो बिल्कुल अलग आयाम में काम करती हैं। वे आंतरिक खुशहाली के लिए मशीनें हैं। जब भी मैं ध्यानिलंग को एक औजार या साधन की तरह कहता हूं, तो लोगों को बुरा लग जाता है, 'सुरु, इसे औजार मत कहिए-हमारे लिए यह भगवान है!' मैं कहता हूं, 'ठीक है-भगवान भी एक साधन है।' जब लोग मंदिर जाकर कहते हैं, 'शिव जी, मेरे लिए यह कीजिए,' तो वे उन्हें अपनी खुशहाली के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग यह नहीं समझते कि एक औजार कितनी जबरदस्त चीज होता है। भगवान उतना जबरदस्त नहीं है-औजार जबरदस्त है। मान लीजिए मैं आपसे किसी फर्नीचर से एक स्क्रू निकालने को कहता हूं-आपके अपने सारे नाखून और कुछ दांत टूट सकते हैं, लेकिन वह स्क्रू नहीं निकलेगा। अगर आपको एक छोटा स्क्रू-ड्राइवर दे दूं- काम हो जाएगा! एक औजार इतना शक्तिशाली होता है-यह आपको ऐसी चीजें करने के योग्य बनाता है जो आप अपने आप नहीं कर सकते। आप अपने सिर के बल खड़े हुए होंगे, हर किस्म की वक्र मुद्राओं में बैठे होंगे, और फिर भी आप ध्यान नहीं कर पाए थे। अब ध्यानिलंग में बैठते हैं, तो आप ध्यानमय हो जाएंगे। तो तमाम लोग जो अपने पूरे जीवन में कभी ध्यान नहीं कर पाते थे, वहां बैठकर ध्यानमय हो जाते हैं। उस दिशा में यह एक शक्तिशाली साधन है-इसीलिए इसे ध्यानिलंग कहते हैं। इसी तरह से, भैरवी एक अलग स्तर पर खुशहाली का साधन हैं। ऐसे परिष्कृत रूप आपको ऐसे स्थान में ले जाने के लिए बनाए गए थे, जहां आप अपने आप से नहीं जा पाएंगे।

उगते सूरज के देश में उगा सुगा

अरुण नैथानी

हाल ही में जापान का राजनीतिक घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि बिना किसी अशांति व चुनाव के नेतृत्व परिवर्तन हो गया। राजा की प्रतिष्ठा वाले देश में एक किसान का बेटा सत्ता शीर्ष पर जा बैठा। गली-गली दरवाजों पर दस्तक देकर जापान की संसद में डायट में जगह बनाने के लिए योशिहिदे सुगा ने वाकई बहुत जूते घिसे। मगर, अब वक्त की कसौटी पर घिस-घिस कर वे कुंदन होकर जापान के सत्ताशीर्ष पर दमकने लगे हैं। ऐसा भी नहीं है कि 'बिल्ली के भाग में छींका फूटा' वाली कहावत चरितार्थ हुई हो। हां, यह जरूर है कि बीते अगस्त में बीमारी के कारण जापान में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने पद छोड़ने की घोषणा कर दी थी। फिर सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने बाकायदा उन्हें अपना नेता चुना और बीते बुधवार को जापानी संसद ने उन्हें देश का प्रधानमंत्री चुन लिया। हालांकि, उम्रदराज योशिहिदे सुगा शिंजो आबे के बेहद करीबी माने जाते हैं। पहली बार जब शिंजो आबे प्रधानमंत्री बने थे तो सुगा उनके साथ थे। फिर वर्ष 2012 में फिर जापान के प्रधानमंत्री बने तो आबे ने सुगा को मुख्य कैबिनेट सेक्रेटरी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। वे पर्दे के पीछे राजकाज चलाने में निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं, खासकर जापानी नौकरशाही के प्रबंधन में सुगा निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। माना जा रहा है कि जापान के इतिहास में दूसरे उम्रदराज प्रधानमंत्री 71 वर्षीय योशिहिदे सुगा आगे शिंजो आबे की नीतियों को लेकर ही आगे चलेंगे। हालांकि, फिलहाल उन्हें कोरोना संकट से जूझना और अगले साल ओलंपिक जैसे विशाल आयोजन का दायित्व भी निभाना है। ठीक एक साल बाद देश में संसदीय चुनाव भी होने हैं। जापान के उत्तर में स्थित स्नोवी में जन्मे सुगा का जन्म एक किसान परिवार में हुआ। उनके पिता स्ट्रॉबरी किसान थे। प्रारंभिक पढ़ाई के बाद अठारह साल की उम्र में उन्होंने टोक्यो छोड़ दिया और एक कार्डबोर्ड फैक्टरी में काम करने लगे। दरअसल, वे विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए अपना खर्च जुटाना चाहते थे। निस्संदेह एक साधारण परिवार में जन्म लेकर जापान के सत्ताशीर्ष तक पहुंचने की सुगा की कहानी कठोर परिश्रम और संघर्ष की बानगी है। उन्होंने जापान की उस राजनीति में जगह बनायी जो अभिजात्य वर्ग के दखल के लिए जानी जाती थी। उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत होसेई विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद संसदीय चुनाव मुहिम में भागीदारी करके की। पहले उन्होंने एलडीपी के एक सांसद के सचिव के रूप में देश के राजनीतिक मिजाज को पढ़ा। फिर देश की सक्रिय राजनीति में उतरे। सबसे पहले वे योकोहामा की सिटी काउंसिल के लिए चुने गये। फिर जापानी संसद के लिए पहली बार 1996 में चुने गये। पहले बड़े दायित्व के रूप में वर्ष 2005 में कोउजुमी सरकार में उन्हें आंतरिक मामलों व संचार विभाग का मंत्री बनाया गया। इसके उपरांत पहली बार प्रधानमंत्री बनने पर शिंजो आबे ने उन्हें वरिष्ठ मंत्री का दायित्व सौंपा। उनका आबे के साथ तालमेल लगातार बना रहा और जब शिंजो आबे दूसरी बार 2012 में प्रधानमंत्री बने तो सुगा को मुख्य कैबिनेट सचिव बनाया गया। शिंजो का दायां हाथ माने जाने वाले सुगा को जापान की जटिल नौकरशाही को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी मिली थी। उनका नौकरशाहों के बीच अच्छा-खासा दबदबा रहा है। मीडिया में उन्हें शिंजो सरकार की 'आयरन वॉल' पुकारा जाता रहा है। उन्हें जापानी प्रशासन का चेहरा माना जाता रहा है। वे कालांतर 14 सितंबर को लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता चुन लिये गये। फिर सोलह सितंबर को जापानी संसद डायट ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री चुन लिया। बहरहाल, अपने बूते जापान की राजनीति में जगह बनाने वाले सुगा के सामने कोरोना संकट के अलावा जापान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी भी है। वे कह चुके हैं कि शिंजो आबे की आर्थिक नीतियों 'आबेनॉमिक्स' को ही आगे लेकर चलेंगे। उनके सामने शिंजो आबे से पहले लंबे समय तक राजनीतिक रूप से अस्थिर रहे जापान में स्थायित्व बनाये रखने की चुनौती भी होगी। उनका मकसद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के संविधान में संशोधन का भी, जिससे मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों से मुकाबले के लिए सुरक्षातंत्र को मजबूत किया जा सके। साथ ही श्रम सुधार, कृषि सुधार के एजेंडे के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में प्राणवायु का संचार करना भी उनका लक्ष्य है। वे देश में पर्यटन संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं। निस्संदेह, सुगा के पास लंबा प्रशासनिक अनुभव है। उन्हें पहले भी पर्दे के पीछे का प्रधानमंत्री कहा जाता रहा है। हालांकि, उन्होंने कहा कि सरकार चलाने में वे शिंजो आबे का मार्गदर्शन लेते रहेंगे, लेकिन वे खुद प्रशासन चलाने में सक्षम हैं। वे दृढ़ व्यक्तित्व वाले राजनेता हैं और पर्दे के पीछे से नौकरशाही को संचालित करते रहे हैं। वे कहते भी रहे हैं कि मैंने शून्य से शुरुआत की है। राजनीति में मेरा कोई परिचित नहीं था।

आज का राशिफल

मेष व्यावसायिक व पारिवारिक समस्याएं रहेंगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। जारी प्रयास सार्थक होंगे। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें। शासन सत्ता से तनाव मिलेगा। गृह सुख में कमी रहेगी।

वृषभ बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। आर्थिक योजनायें सफल होंगी। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे। वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

मिथुन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। उदर विकार या नेत्र विकार की संभावना है। पारिवारिक जनों से पीड़ा मिलने के योग हैं। वाणी की सौम्यता व्यर्थ के विवादों से आपको बचा सकती है।

कर्क पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खान-पान में संयम रखें। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे।

सिंह पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। क्रोध व भावुकता में लिया गया निर्णय कष्टकारी होगा। अनावश्यक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। धन लाभ की संभावना है।

कन्या पारिवारिक जनों का सहयोग मिलेगा। मांगलिक कार्यों में सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी।

तुला जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।

वृश्चिक परिवारिक जीवन सुखमय होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे।

धनु पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा।

मकर आर्थिक दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। संतान के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। वाद विवाद की स्थिति आपके हित में न होगी।

कुम्भ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। किया गया परिश्रम सार्थक होगा। रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी रखें। भारी व्यय का सामना करना पड़ेगा। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

मीन व्यावसायिक दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। वाणी की असभ्यता आपको किसी संकट में डाल सकती है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शासन सत्ता के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहेंगे। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

कंपनियों में लगी नए प्रोडक्ट उतारने की होड़, आईटीसी ने 5 महीनों में लॉन्च किए 40 नए प्रोडक्ट

नई दिल्ली। कोरोना वायरस देश की पैकेज्ड गुड्स कंपनियों के लिए अवसर लेकर आई है। कोरोना काल के दौरान लोगों में ऐसी चीजों की अधिक डिमांड होने लगी जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार हो। अप्रैल से अगस्त तक पांच महीनों में इन कंपनियों ने दर्जनों नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। इनमें वेजिटेबल वॉशेज से लेकर इम्युनिटी बढ़ाने वाले जूस और हल्दी आइसक्रीम शामिल हैं। पैकेज्ड फूड सेक्टर की देश की तीसरी सबसे बड़ी सूचीबद्ध कंपनी आईटीसी ने पिछले 5 महीनों में 40 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। इनमें सब्जियां और फर्श साफ करने वाले उत्पाद और इम्युनिटी बेवरेज शामिल हैं। पिछले पूरे साल कंपनी ने कुल 60 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए थे। आईटीसी के चेयरमैन संजीव पुरी ने पिछले महीने एजीएम में कहा था कि उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इस महामारी के दौरान कंपनी का पूरा जोर इनोवेशन पर है। कंपनी के सैनिटाइजर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 275 गुना बढ़ाया गया है। विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग के प्रेजिडेंट (कंज्यूमर केयर बिजनेस) अनिल चुग ने कहा, अप्रैल 2020 से नए प्रोडक्ट हमारे लिए बेहद अहम रहे हैं। इस दौरान कंपनी ने साबुन, हैंडवॉश, सैनिटाइजर, डिसइनफेक्टेंट्स, एंटी जर्म डिटरजेंट्स और फैब्रिक कंडीशनर्स लॉन्च किए हैं। हल्दी के बारे में आयुष मंत्रालय के जारी एडवाइजरी से भी इससे जुड़े प्रोडक्ट्स के लॉन्च में तेजी आई। अमूल ने हल्दी आइसक्रीम और हल्दी मिल्क लॉन्च किया। डाबर के सीईओ मोहित मल्होत्रा ने कहा, कोरोना महामारी के फैलने के बाद हमने तीन महीने में 40 से अधिक नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। इसी तरह मैरिको ने हनी, टर्मरिक मिल्क मिक्स और हल्दी-जिंजर मिल्क बाजार में उतारा है।

उड़ानों की संख्या 1,400 के करीब

नई दिल्ली। देश में उड़ानों की संख्या बढ़ते हुए गुरुवार को 1,400 के करीब पहुंच गई जबकि पूर्णबंदी के बाद से अब तक यात्रियों की कुल संख्या 91 लाख के पार पहुंच गई है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 17 सितंबर को घरेलू मार्गों पर कुल 1,383 नियमित यात्री उड़ानें रवाना हुईं जिनमें 1,16,398 यात्रियों ने सफर किया। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि पूर्णबंदी के उपरांत 25 मई को घरेलू उड़ानें दुबारा शुरु होने के बाद से 91 लाख से अधिक यात्री सफर कर चुके हैं। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा ''घरेलू नागर विमानन परिचालन निर्बाध रूप से चल रहा है। गत 17 सितंबर को 1,16,398 यात्रियों के साथ हम धीरे-धीरे कोविड-पूर्व स्तर की ओर बढ़ रहे हैं। परिचालन दुबारा शुरु होने के बाद 25 मई से अब तक 91 लाख से अधिक यात्री हवाई सफर कर चुके हैं।

कोविड-19 संबंधित बीमा उत्पादों की अवधि बढ़ाने पर इरडा लेगा फैसला: चेयरमैन

नई दिल्ली। इरडा के चेयरमैन सुभाष सी खुंटिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि नियामक कोविड-19 से जुड़े बीमा उत्पादों की अवधि बढ़ाने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। इसका कारण इसके टीके के आने में लगने वाला समय है। इसके अलावा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) कोरोना वायरस के लिये मानक उत्पाद की दिशा में भी काम कर रहा है। यह उत्पाद पॉलिसीधारकों के लिये आसान होगा और उसके लिये भारी- भरकम पॉलिसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। सीआईआई के डिजिटल तरीके से आयोजित बीमा और पेंशन सम्मेलन में खुंटिया ने कहा, 'कोविड-19 संबंधित उत्पादों की समयसीमा बढ़ाने के संदर्भ में, हम उम्मीद कर रहे थे कि टीका आने में लंबा समय नहीं लगेगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसमें कुछ और समय लगेगा। इसको देखते हुए हम उपयुक्त समय पर पॉलिसी की अवधि बढ़ाने के बारे में निर्णय करेंगे।' उल्लेखनीय है कि कोरोना कवच नाम से 10 जुलाई को बीमा उत्पाद पेश किश गया था। इसकी पेशकश साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियां दोनों कर रही हैं।

भारत में खुलेगा एप्पल का पहला ऑनलाइन स्टोर, 23 सितंबर को होगा लॉन्च

बिजनेस डेस्क।

एप्पल ने शुक्रवार को कहा कि वह अगले हफ्ते भारत में अपने ऑनलाइन स्टोर की शुरुआत करेगी। इस पहल से एप्पल को त्योहारी मांग का फायदा उठाने में मदद मिलेगी। तकनीकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ने बताया कि 23 सितंबर को शुरू होने वाले नए ऑनलाइन स्टोर से ग्राहकों को दुनिया भर में फैले एप्पल स्टोर के समान सेवाएं मिलेंगी। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने फरवरी में कहा था कि कंपनी इस साल के अंत में भारत में अपना ऑनलाइन स्टोर शुरू करेगी, जबकि उसका पहला पारंपरिक खुदरा स्टोर 2021 में चालू होगा। एप्पल की वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिडेर ओ ब्रायन ने कहा, 'हम जानते हैं कि हमारे उपयोगकर्ता जुड़े रहने, सीखने और रचनात्मकता का इस्तेमाल करने के लिए प्रौद्योगिकी पर भरोसा कर रहे हैं, और भारत में एप्पल स्टोर को ऑनलाइन लाकर, हम इस महत्वपूर्ण समय में अपने ग्राहकों को एप्पल की बेहतरीन पेशकश दे रहे हैं।' एप्पल इस समय भारत में अपने उत्पादों को तीसरे पक्ष के विक्रेताओं और फ्लिपकार्ट तथा अमेजन जैसे ऑनलाइन मार्केटप्लेस के जरिए बेचती है। केंद्र सरकार ने पिछले साल एकल-ब्रांड खुदरा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के दिशानिर्देशों में ढील दी थी ।

केंद्र सरकार ने पिछले साल एकल-ब्रांड खुदरा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के दिशानिर्देशों में ढील दी थी, जिसके तहत कंपनियों के लिए स्थानीय स्तर पर आउटसोर्सिंग के नियमों को आसान बनाया गया। सरकार के इस कदम के बाद एप्पल ने कहा था कि वह अपने वैश्विक मानकों के अनुरूप भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए ऑनलाइन और पारंपरिक स्टोर खोलने की इच्छुक है। कंपनी ने बयान में कहा कि ग्राहक इन स्टोर के जरिए सलाह पा सकते हैं और नए उत्पादों के बारे में सीधे ऐपल से सीख सकते हैं।

फेसबुक और इंस्टाग्राम हुए डाउन, लोगों को लॉग इन करने में हुई परेशानी

नई दिल्ली। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक पर गुरुवार रात को कुछ देर के लिए ठप रहे। लोगों को लॉग इन करने में परेशानी हुई। यूजर्स को फोटो वीडियो और समाचार फीड लोड करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं भारत समेत दुनियाभर के यूजर्स को एंड्रॉयड और आईओएस पर इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का उपयोग करने में परेशानी हुई। वो इन प्लेटफॉर्म पर रिफ्रेश नहीं कर पा रहे थे। साथ ही न तो संदेश भेज पा रहे थे न ही फोटो साझा कर पा रहे थे। डाउनडेक्टर के अनुसार, यह तकनीकी गड़बड़ करीब रात 11 बजे हुई। यह एक साइट है जो तमाम आउटेज को ट्रैक करती है। कई यूजर्स ने ट्विटर पर सोशल साइटों की दिक्कतों के बारे में लिखा, साथ ही हैशटैग और सका उपयोग करते हुए फेसबुक और इंस्टाग्राम के ठप हो जाने से अपनी समस्याओं के बारे में लिखा। वहीं ट्विटर पर कई यूजर्स अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे थे। एक यूजर्स ने लिखा कि उन्हें फेसबुक पर फोटो अपलोड करने में देरी हो रही है और वह फेसबुक लाइव पर एरर आ रहा है। कुछ इंस्टाग्राम के यूजर्स ने लिखा कि न्यूज फीड को रिफ्रेश करने में बहुत देर तक कुछ नहीं आ रहा है।

दिवाना कानून के तहत जून तक 250 दबाव वाली कंपनियों को बचाया गया: साहू

नई दिल्ली। भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के चेयरपर्सन एम. एस. साहू ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिवाला कानून के तहत समाधान योजना के जरिए जून 2020 तक करीब 250 कर्ज बोझ तले दबी कंपनियों को बचाया गया। इस कानून का मूल उद्देश्य ही कंपनियों को जिंदा रखना है। दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) को लागू हुए चार वर्ष हो चुके हैं। यह कानून दबाव वाली परिसंपत्तियों के समयबद्ध और बाजार से जुड़े समाधान की सुविधा देता है। कोविड-19 संकट के दौरान दिवाला प्रक्रिया के प्रावधान निलंबित करने के बारे में साहू ने कहा कि एक सीमित और सुस्पष्ट सनसेट नियम के साथ प्रक्रिया में सुधार की जरूरत थी। साहू ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम में कहा कि जून 2020 तक आईबीसी ने करीब 250 दबाव वाली फर्मों का समाधान योजना के माध्यम से बचाव किया है। इसमें से करीब एक तिहाई कंपनियां तो भारी दबाव से जूझ रही थी। इन कंपनियों को बचाने से इनके ऋणदाताओं ने प्रक्रिया में प्रवेश करने के समय इनके परिसमापन मूल्य का करीब 200 प्रतिशत तक वसूल किया। उन्होंने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में यह संहिता असफल कंपनी के माले में बाजार ताकतों को अनुपूरक उपचार में सक्षम बनाता है वहीं वहनीय कंपनी को बचाने और ऐसी कंपनी जो व्यवहार्य नहीं रह गई है।

बीएसएनएल के मोबाइल नेटवर्क में 53फीसदी इक्विपमेंट चीनी कंपनियों की, राज्यसभा में सरकार ने दी जानकारी

बिजनेस डेस्क।

सरकार ने यह स्वीकार किया है कि भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के मोबाइल नेटवर्क में करीब 53 फीसदी इक्विपमेंट दो चीनी कंपनियों जेटीई और हुवावे से है। इस मामले में निजी कंपनियों की स्थिति बेहतर है क्योंकि वे कई देश से ऐसे उपकरण मंगाती हैं। बीएसएनएल के मोबाइल नेटवर्क में करीब 44 फीसदी इक्विपमेंट (उपकरण और अन्य साजोसामान) चीन की कंपनी से और 9 फीसदी इक्विपमेंट हुवावे से है। संचार राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने गुरुवार को राज्यसभा में यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि चीनी टेलीकॉम गियर मेकर्स कंपनियों उपकरणों के बारे में सरकार के पास डेटा नहीं है। धोत्रे ने राज्यसभा में बताया, के मोबाइल नेटवर्क का 44.4 फीसदी हिस्सा से और 9 फीसदी हिस्सा हुवावे से है। इसी तरह महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के मोबाइल नेटवर्क में 10 फीसदी हिस्सा चीनी कंपनियों से आए इक्विपमेंट का है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आंकड़ों के आधार पर उन्होंने बताया कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम अपनी सेवाओं के लिए जेटीई और हुवावे का कोई भी इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं कर रही है। जरूरतों के हिसाब से टेलीकॉम इक्विपमेंट खरीदती हैं और ऐसी कंपनियों को लाइसेंस में दिए गए सुरक्षा प्रावधानों का पालन करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि टेलीकॉम कंपनियां अपनी कारोबारी जरूरतों के हिसाब से टेलीकॉम इक्विपमेंट खरीदती हैं और ऐसी कंपनियों को लाइसेंस में दिए गए सुरक्षा प्रावधानों का पालन करना पड़ता है।

दूसरी निजी कंपनियों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अपने नेटवर्क में कई वेंडर से खरीदे गए इक्विपमेंट का इस्तेमाल करती है और हमेशा सुरक्षा संबंधी मानकों का पालन करती रही है। इसी तरह भारती एयरटेल भारत, अमेरिका, यूरोप, चीन जैसे कई देशों की कंपनियों के इक्विपमेंट का इस्तेमाल करती है।

भारत के प्याज निर्यात पर रोक, नेपाल-बांग्लादेश के निकले आंसू

बिजनेस डेस्क। भारत सरकार ने सब्जियों खासकर प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए प्याज निर्यात पर रोक क्या लगाई, पड़ोसी देशों की आंखों से आंसू निकलने लगे। खासकर बांग्लादेश और नेपाल में प्याज की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। बांग्लादेश ने तो किसी सूचना के बिना प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के मोदी सरकार के फैसले पर आधिकारिक रूप से अपनी 'गहरी चिंता' जताई है। इसे देखते हुए वहां की सरकार ने भारत से प्याज के निर्यात पर से बैन हटाने का अनुरोध किया है। उधर पड़ोसी देश नेपाल में भी भारत सरकार की ओर से निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद प्याज की कीमतें आसमान चढ़ गई हैं। कुछ दिन पहले तक 20-30 रुपए किलो बिकने वाले प्याज की खुदरा कीमत यहां 150 रुपए किलो तक पहुंच गई है। कई जगहों पर व्यापारियों ने जमाखोरी और कालाबाजारी शुरू कर दी है। ऐसे में आने वाले दिनों में इसकी कीमत और अधिक बढ़ सकती है। भारत दक्षिण एशिया में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मलेशिया भारतीय प्याज पर निर्भर हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार को भेजे पत्र में कहा है कि प्याज के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला 2019 और 2020 में दोनों देशों के बीच बनी आपसी समझ के अनुरूप नहीं है।

विदेशी कंपनियों का कारखानों को चीन से बाहर ले जाना सामान्य बाजार घटना: चीनी अधिकारी

बीजिंग।

चीन के योजना विभाग की एक अधिकारी ने इस बात को माना कि विदेशी कंपनियां बढ़ती लागत तथा अमेरिका के साथ व्यापार तनाव बढ़ने के कारण अपने विनिर्माण कारखानों को चीन से हटाकर अन्य देश ले जा रही हैं। हालांकि, उसने इसे एक सामान्य बाजार गतिविधि बताया है। चीन के राष्ट्रीय विकास एवं सुधार आयोग (एनडीआरसी) की प्रवक्ता मेंग वेई ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा व्यापक स्तर पर विनिर्माण संयंत्र बंद करने की घटना को कम आंकने का प्रयास किया। हालांकि, इन कंपनियों का चीन को दशकों से वैश्विक निर्यात केंद्र बनाने व वृहद स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित कराने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने बुधवार को कहा कि चीन से उत्पादन आधार को स्थानांतरित करने के अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के हालिया कदमों को सामान्य बाजार गतिविधियों के रूप में देखा जा सकता है। मेंग ने कंपनियों की बढ़ती लागत और चीन व अमेरिका के बीच व्यापार तनाव में तेजी को इसके लिये जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि चीन अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक खुला बनाने और विदेशी व्यवसायों के लिये व्यवस्था में सुधार करने को प्रतिबद्ध है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने मेंग के हवाले से कहा, 'यह एक सामान्य बाजार घटना है।' उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस महामारी के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन के प्रति कठोर नीतियां अपनाने से चीन पिछले दो वर्षों से आपूर्ति श्रृंखला में बड़े व्यवधानों से जूझ रहा है। ट्रंप ने मई में चीन के साथ व्यापार समझौते पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया था। भारत, वियतनाम और बांग्लादेश सहित कई देशों ने चीन छोड़ने वाली विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिये विशेष नीतियों की घोषणा की है। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच साल के पहले छमाही में आपसी निवेश लगभग एक दशक में सबसे निचले स्तर पर आ गया। रोडियम ग्रुप तथा गैर लाभकारी संस्था नेशनल कमिटी ऑन यूएस चाइना रिलेशंस की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्यक्ष व उद्यम पूंजी निवेश 30 जून को समाप्त छमाही में अनुमानित तौर पर गिरकर 10.9 अरब डॉलर पर आ गया।

यह 2016 में 26 अरब डॉलर के अपने शीर्ष स्तर पर था। रिपोर्ट के अनुसार, चीन में अमेरिकी कंपनियों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश इस साल के पहले छह महीनों के दौरान 4.1 अरब डॉलर तक गिर गया।

1 लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना से मिलेगा 90,000 से अधिक लोगों को रोजगार

अहमदाबाद। एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली महत्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को क्रियान्वित करने वाले नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन (एनएचएसआरसीएल) ने आज कहा कि इसके निर्माण के दौरान ही प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनो मिलाकर 90 हज़ार से अधिक रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। कारपोरेशन की प्रवक्ता सुषमा गौर ने आज जारी बयान में कहा कि निर्माण सम्बंधी काम के लिए 51000 से अधिक टेक्निशियन तथा कुशल और अकुशल कामगारों की ज़रूरत होगी। कारपोरेशन ऐसे लोगों को विभिन्न सम्बंधित कामों के लिए प्रशिक्षण देने की सम्भावनाएं तलाश रहा है। पटरी बिछाने के लिए कारपोरेशन ठेकेदारों के कर्मियों के विशेष प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करेगा। उन्होंने बताया कि निर्माण के दौरान 34000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे। 480 किमी से अधिक लम्बी इस पटरी में 460 किमी लम्बा वायाडक्ट (ज़मीन के ऊपर बनी पुलनुमा संरचना) और समुद्र के नीचे 7 किमी समेत कुल 26 किमी लम्बी सुरंगें, 27 लोहे के पुल, 12 स्टेशन और कई अन्य सहायक सुपर संरचनायें होगी।

बेरोजगारी का बढ़ता संकट- मई-अगस्त में गई 66 लाख की नौकरियां

बिजनेस डेस्क।

देश भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है, बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। इसी बीच एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई है कि पिछले 4 महीनों में 66 लाख वाइट कॉलर जॉब करने वालों की नौकरियां चली गई हैं। मई से अगस्त के बीच 66 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, एकाउंटेंट, विश्लेषक समेत कई सेक्टर के पेशेवरों की नौकरी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016 के बाद से रोजगार अपने सबसे न्यूनतम स्तर आ गई है। साप्ताहिक विश्लेषण के आधार पर यह सर्वे जारी किया गया है। यह सर्वे हर चार महीने में किया जाता है। सैलरीड कर्मचारियों में सबसे बड़ा रोजगार का नुकसान व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल और अन्य कर्मचारियों का हुआ है। देश में मई-अगस्त 2019 के दौरान व्हाइट कॉलर कर्मचारियों की संख्या 18.8 मिलियन थी। मई-अगस्त 2020 में इसमें 12.2 मिलियन की कमी आई है। साल 2016 के बाद इन प्रोफेशनल्स में यह सबसे कम स्तर है। सीएमआईई ने कहा कि पिछले चार सालों में लॉकडाउन में सबसे ज्यादा गिरावट रोजगार में देखी गई है। सीएमआईई की रिपोर्ट के अनुसार केवल जुलाई महीने में ही 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल में अब तक 1 करोड़ 89 लाख लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। इससे पहले सीएमआईई ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अप्रैल 2020 में 17.7 मिलियन लोगों की नौकरी चली गई थी, वहीं मई में यह आंकड़ा 0.1 मिलियन का रहा। इसके बाद जून में लगभग 3.9 मिलियन लोगों को नौकरी वापस मिली। सीएमआईई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह स्थिति बहुत विपरीत है और बहुत ही कम उम्मीद है कि वेतनभोगी लोगों को दोबारा से नौकरी मिलेगी। रिपोर्ट में संदेह जताया गया है कि जितनी बड़ी तादाद में लोगों की नौकरियां गई हैं उतनी तादाद में नौकरियां वापस मिलने की संभावना नहीं है। लॉकडाउन के दौरान वेतनभोगी लोगों की नौकरी पर काफी असर पड़ा वे बेरोजगार हो गए। असंगठित क्षेत्रों में स्थिति और भी गंभीर है। 2019-20 में वेतनभोगी नौकरियां औसतन लगभग 190 लाख थीं।

लेकिन पिछले वित्त वर्ष में इसकी संख्या कम होकर अपने स्तर से 22 प्रतिशत नीचे चली गई।

भारत-अमेरिका के बीच रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी की जड़ें हुईं मजबूत :राजदूत संधू

वाशिंगटन।

अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी ने बहुत कम समय में गहरी जड़ें जमा ली हैं और इस सहयोग से दोनों देशों में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। संधू ने कहा कि भारत के 1.3 अरब लोगों की विकास संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करने में अमेरिका एक महत्वपूर्ण साझेदार है और मानवीय प्रयासों का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जहां भारत और अमेरिका के बीच आपसी सहयोग नहीं है। संधू ने अमेरिकी ऊर्जा विभाग द्वारा आयोजित 2020 के प्राकृतिक गैस शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए गुरुवार को कहा कि आपसी संबंधों के लिहाज से कुछ क्षेत्र हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण बनकर उभरे हैं संबोधित करते हुए गुरुवार को कहा कि आपसी संबंधों के लिहाज से कुछ क्षेत्र हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण बनकर उभरे हैं और ऊर्जा ऐसा ही क्षेत्र है। शिखर सम्मेलन को अमेरिकी ऊर्जा मंत्री डैन ब्रोइलेट और व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय आर्थिक परिषद की निदेशक लैरी कुडलो ने भी संबोधित किया। संधू ने कहा, 'यह जानकर खुशी होगी कि दो साल से कम अवधि में हमारी रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी ने गहरी जड़ें जमा ली हैं। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। हमारी ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ेगी, क्योंकि हम प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) के दूरदर्शी नेतृत्व में विकास की गति को आगे बढ़ रहे हैं।' उन्होंने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, और अमेरिका प्राकृतिक गैस सहित ऊर्जा संसाधनों और अग्रणी प्रौद्योगिकियों से संपन्न है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा साझेदारी से दोनों देशों में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की प्रक्रिया भी तेज हो सकती है। भारत अब अमेरिकी कच्चे तेल के लिए चौथा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय बाजार है और अमेरिकी एलएनजी के लिए पांचवां सबसे बड़ा बाजार है।

एसपी ग्रुप ने टाटा संस को भेजा लीगल नोटिस, फंड जुटाने से रोकने का लगाया आरोप

नई दिल्ली ।

शापूरजी पालनजी (एसपी) ग्रुप इस वक्त कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। कर्ज के बोझ को कम करने के लिए एसपी ग्रुप ने टाट संस के शेयरों को गिरवी रखकर फंड जुटाने की योजना बनाई थी। उनकी फंड जुटाने की इस योजना पर टाटा संस ने पानी फेर दिया था। अब एसपी ग्रुप ने टाट संस को नोटिस भेजा है। एसपी ग्रुप द्वारा भेजे गए लीगल नोटिस में बोर्ड सदस्यों की सहभागिता पर सवाल खड़े किए हैं। एसपी ग्रुप ने कहा है कि टाटा संस में मिस्त्री ग्रुप की शेयर होल्डिंग के बदले फंड जुटाने से रोकना एक उत्पीड़न कदम है। क्या टाटा संस ने बोर्ड की सहमति से यह कदम उठाया है, इस बारे में एसपी ग्रुप ने स्पष्टीकरण मांगा है। एसपी ग्रुप के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि टाट संस के बोर्ड सदस्यों को इस लीगल नोटिस का जवाब देने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। बोर्ड के सदस्य अगर जवाब देने में नाकाम रहते हैंतो एसपी ग्रुप उचित कार्रवाई करेगा। इसमें एसपी ग्रुप को नुकसान पहुंचाने की भरपाई के लिए दावा भी शामिल है। एसपी ग्रुप ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब वह स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर लिमिटेड (एसडब्ल्यूएसएल) को भुगतान में डिफॉल्ट हो गया है। एसपी ग्रुप को एसडब्ल्यूएसएल को 1000 करोड़ रुपए का भुगतान करना था, लेकिन वह केवल 103 करोड़ रुपए भुगतान कर पाया है। इस महीने के अंत में भुगतान करना है। टाटा संस ने शेयरों की गिरवी रोकने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पांच सितंबर को टाटा संस ने याचिका दाखिल कर शेयरों की गिरवी रखने की मांग की है। टाटा संस को डर है कि गिरवी रखे गए शेयर भविष्य में ट्रांसफर हो सकते हैं। टाटा संस की मानें तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तहत यदि कोई सदस्य कंपनी के शेयर बेचना चाहता है तो उन शेयरों को उचित बाजार मूल्य पर खरीदने के संबंध में टाटा संस के बोर्ड को इनकार करने का अधिकार है। टाटा संस के बाद एसपी ग्रुप ने भी 7 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। एसपी ग्रुप का आरोप है कि टाटा संस ने यह कदम उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए उठाया है। एसपी ग्रुप के प्रवक्ता का कहना है कि टाटा संस के गलत इरादे इस बात से स्पष्ट हो जाते हैं कि तत्काल याचिका दाखिल करने के बाद गलतियों को ठीक करने के लिए आवेदन को होल्ड कर दिया है। बता दें कि टाटा ग्रुप के बोर्ड और बड़े निवेशकों ने एसपी ग्रुप के साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से हटा दिया था। तभी से दोनों कॉरपोरेट घरानों के बीच विवाद चल रहा है। बोर्ड ने साइरस मिस्त्री पर खराब प्रबंधन का आरोप लगाया था। पद से हटाने के दो महीने बाद मिस्त्री परिवार की दो इन्वेस्टमेंट कंपनियों ने एनसीएलटी की मुंबई बेंच में अपील दायर की थी।

आईटीएटी ने अप्रैल- अगस्त के बीच 5,392 मामलों का निपटारा किया

नई दिल्ली।

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने अप्रैल से अगस्त 2020 अवधि के दौरान 5,000 से अधिक कर मामलों का निपटारा किया। बृहस्पतिवार को जारी एक आधिकारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। इसमें कहा गया, 'इस अवधि के दौरान जब धीरे धीरे लॉकडाउन को उठाने की शुरुआत हो रही थी तब अप्रैल से 31 अगस्त 2020 तक 5,392 मामलों का निपटारा किया गया जबकि इस दौरान 3,078 मामले दर्ज किये गये।' विज्ञप्ति में कहा गया कि आईटीएटी ने ऐसे समय जब सुरक्षा चिंताओ को ध्यान में रखते हुये सशरीर उपस्थित होकर मामलों की सुनवाई नहीं हो सकती थी तब प्रत्यक्ष कर मामलों में न्याय के लिये सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक का पूरी सक्रियता के साथ इस्तेमाल किया गया। आईटीएटी की 63 पीठ देश के 28 नियमित केन्द्रों में फैली हुई हैं और वाराणसी और देहरादून में दो सर्किट पीठें भी हैं। प्रशासनिक तौर पर ये पीठें 10 क्षेत्रों में बंटी हैं और प्रत्येक का नेतृत्व उपाध्यक्ष करते हैं। आइटीएटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पीपी भट्ट ने लॉकडाउन उठने की शुरुआत होने पर वीडियो कन्फ्रेंस के जरिये न्यायिक प्रक्रि या शुरू करने का निर्देश दिया था।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

Sports

चोट के कारण नाओमी ओसाका फ्रेंच ओपन से बाहर

पेरिस । अमेरिकी ओपन चैम्पियन नाओमी ओसाका ने बाएं पैर की 'हैमस्ट्रिंग' चोट के कारण फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंडस्लैम से हटने का फैसला किया। इससे पेरिस में 27 सितंबर से शुरू हो रहे फ्रेंच ओपन में ओसाका और गत चैम्पियन एश बार्टी हिस्सा नहीं लेंगी। क्ले ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट के आयोजकों ने दर्शकों की संख्या में और कटौती करने का फैसला किया है क्योंकि फ्रेंच में कोरोना वायरस महामारी से हालात बिगड़ रहे हैं। आयोजकों ने कहा कि अब पेरिस पुलिस विभाग ने दर्शकों की संख्या 5000 दर्शक प्रतिदिन कर दी है। ओसाका तीसरी रैंकिंग पर काबिज हैं। पिछले महीने वेस्टर्न एवं सदर्न ओपन के दौरान वह 'हैमस्ट्रिंग' में चोट लगा बैठी थीं और इसी के कारण उन्होंने टूर्नामेंट के फाइनल से हटने का फैसला किया। अमेरिकी ओपन में भी वह काफी ज्यादा पट्टियां बांधकर खेल रही थीं। ओसाका ने अपने ट्विटर पर लिखा- दुर्भाग्य से मैं इस साल फ्रेंच ओपन में नहीं खेल पाऊंगी। उन्होंने लिखा- मेरी हैमस्ट्रिंग में अब भी दर्द है इसलिए मेरे पास क्ले कोर्ट की तैयारी के लिये समय नहीं होगा।

डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट

ओलिंपिक सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने टूर्नामेंट से नाम वापस लिया, नवंबर में एशिया चैम्पियनशिप में खेल सकती हैं

लंदन ।

भारतीय शटलर और ओलिंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने डेनमार्क ओपन से नाम वापस ले लिया है। हालांकि, कोरोना के कारण यह टूर्नामेंट अनिश्चितकाल के लिए टल चुका है। पहले यह टूर्नामेंट 13 से 18 अक्टूबर तक ओडेंस में होने वाला था। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बाई) ने इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए खिलाड़ियों की राय मांगी है। इसी दौरान सिंधु ने टूर्नामेंट में नहीं खेलने की बात कही। हालांकि वह नवंबर में होने वाले एशिया ओपन- और एशिया ओपन- में खेल सकती हैं।

साइना समेत दूसरे भारतीय खिलाड़ी डेनमार्क ओपन खेलेंगे

बाई ने डेनमार्क ओपन के लिए खिलाड़ियों को इंट्री फॉर्म भेजकर सहमति मांगी थी। इसमें उन्हें यह लिखकर देना था कि कोरोना के बीच वह टूर्नामेंट के लिए यात्रा करने के लिए तैयार है। एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि किदांबी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, साइना नेहवाल, पारुपल्ली कश्यप और सुभंकर डे ने अपनी सहमति भेज दी है।

जबकि सिंधु ने अपनी सहमति नहीं दी है। सिंधु ने थॉमस कप से भी नाम वापस ले लिया था, लेकिन बाद में राजी हो गईं 2021 तक के लिए टल चुके थॉमस और उबेर कप से भी सिंधु ने अपना नाम वापस ले लिया था। जबकि सिंधु ने अपनी सहमति नहीं दी है। सिंधु ने थॉमस कप से भी नाम वापस ले लिया था, लेकिन बाद में राजी हो गईं 2021 तक के लिए टल चुके थॉमस और उबेर कप से भी सिंधु ने अपना नाम वापस ले लिया था।

लेकिन बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया(बाई) के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा के अनुरोध पर खेलने के लिए तैयार हो गई थी।पहले यह टूर्नामेंट 3 से 12 अक्टूबर तक होना था। इंडोनेशिया समेत कोरिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ताईवान, इंडोनेशिया समेत कोरिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ताईवान, सिंगापुर और हांगकांग जैसे बड़े देश भी टूर्नामेंट से हट चुके हैं।

फुटबॉल : टॉटेनहम, एसी मिलान ने यूरोपा लीग क्वालिफाइंग में हासिल की जीत

लंदन ।

टॉटेनहम ने एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए आखिरी मिनटों में दो गोल कर यूरोपा लीग क्वालीफाइंग के दूसरे चरण के मुकाबले में नौ खिलाड़ियों के साथ खेल रहे लोकोमोटिव प्लोवदिव को 2-1 से हराया। एसी मिलान और रेंजर्स ने भी दूसरे दौर के मुकाबलों में जीत दर्ज की। मैच के 71वें मिनट में जी. मिनचेव के गोल से लोकोमोटिव प्लोवदिव ने टॉटेनहम पर बढ़त बना ली लेकिन 80वें मिनट में कप्तान हैरी केन ने पेनल्टी को गोल में बदल कर स्कोर 1-1 कर दिया। इसके पांच मिनट बाद स्थापन्न खिलाड़ी तेंगाय नडोमबेले ने टीम की बढ़त को 2-1 कर दिया जो आखिर तक कायम रहा। इस बीच लोकोमोटिव प्लोवदिव के दो खिलाड़ियों (78वें और 79वें मिनट) को रेड कार्ड दिखाया गया जिसके कारण टीम को नौ खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। एसी मिलान ने डब्लिन में खेले गए मैच में शेमरॉक रोवर्स को 2-0 से हराया। टीम के लिए ज्लाटन इब्राहिमोविच और हकन काल्हनोग्लु ने गोल दागे। ज्लाटन इब्राहिमोविच और हकन काल्हनोग्लु ने गोल दागे। रेंजर्स ने लिंकन रेड्स इम्प्स को जिब्राल्टर में खेले गये मैच में 5-0 की करारी शिकस्त दी।

कोरोना वारियर्स के लिए आगे आई दिल्ली कैपिटल्स टीम, जर्सी की समर्पित

नई दिल्ली । आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने कहा कि उसके खिलाफ यूएई में इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान जो जर्सी पहनेंगे उस पर 'थैंक्यू कोविड वारियर्स' लिखा होगा जो कोरोना महामारी के बीच काम पर डटे कोरोना योद्धाओं के जज्बे को उनका सलाम होगा। आईपीएल की शुरूआत शनिवार को चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच पहले मैच से होगी। दिल्ली टीम ने एक बयान में कहा- दिल्ली कैपिटल्स की आधिकारिक मैच जर्सी पर 'थैंक्यू कोविड वारियर्स' लिखा होगा और पूरे सत्र में टीम यही जर्सी पहनेगी। दिल्ली कैपिटल्स के सीनियर तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा, स्पिनर अमित मिश्रा और सहायक कोच मोहम्मद कैफ ने वर्चुअल मीट में कुछ कोरोना योद्धाओं से बात भी की जिनमें डॉक्टर और पुलिस अधिकारी शामिल थे। ईशांत ने विज्ञप्ति में कहा- सभी सफाईकर्मियों, डॉक्टरों, सुरक्षाबलों, रक्तदान करने वालों, समाजसेवियों, डॉक्टरों और उनके परिवारों को यह मानवता की सेवा के लिए हमारा सलाम है। अमित मिश्रा ने कहा- इन कोरोना योद्धाओं को धन्यवाद देने के लिए शब्द काफी नहीं है। आप सभी को हमारा सलाम। आपके काम प्रेरित करते रहेंगे। कैफ ने कहा- जिंदगी की इस लड़ाई में दूसरों को खुद से आगे रखने के लिए बड़ा जज्बा और निस्वार्थ भाव चाहिए होता है। दुनिया को बेहतर बनाने के लिये मैं आप सभी को सलाम करता हूं।

श्रीनगर में संपन हुई तीन दिवसीय इंटर जोनल फुटबाल टूर्नामेंट

श्रीनगर।

श्रीनगर में युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित तीन दिवसीय फुटबाल टूर्नामेंट संपन्न हो गई। यह टूर्नामेंट अलग-अलग वैन्यू पर आयोजित की गई थीं। यू14 के तहत मैच बायज हायर सकेंडरी स्कूल जैछबल में खेले गये जबकि यू17 के तहत मैंच पोलेग्राउंड में खेले गये। वहीं यू19 के मैच गिनदुन स्टेडियम में आयोजित किये गये। समापन समारोह पर विभाग के अधिकारियों ने विजेताओं को ईनाम बांटे। यू14 फुटबाल परिणामू-इस टूर्नामेंट में तीन मैच खेले गये। पहले दिन जोन हवल ने जोन ईदागाह को हराया। जोन गुलाबगढ़ ने जोन रेनावारी को औरजोन बटमालू ने जोन निशान को हराया। वहीं दूसरे दिन जोन अमीराकदल ने जोन जलदगार को, जोन बटमालू ने गुलाबाग और जोन अमीराकदल ने जोन हवल को हराया। तीसरे दिन के मैच में अंतिम दिन जोन बटमालू ने जोन अमीराकदल पर विजय पाई। यू17 के परिणाम-पहले दिन के मैच में जोन बटमालू ने जोन ईदगाह को हराया। जोन हवल ने गुलाबबाग को और जोन अमीराकदन ने जलदागर को हराया। दूसरे दिन जोन रैनावारी ने जोन निशात को हराया। जोन अमीराकदल ने जोन हवल को हराया और जोन बटमालू ने जोन रैनवारी को हराया। वहीं तीसरे दिन के परिणाम कुछ यूं रहे-जोन अमीराकदल ने जोन बटमालू पर जीत हासिल की। यू19 के परिणाम-पहले दिन के मैच में जोन अमीराकदल ने जोन इदगाह को हराया।

जोन निशात को जोन गुलाबबाग ने हराया औरजोन हवल से जोन जलदगार हार गया। दूसरे दिन मैच में बटमालू ने रैनावारी को पछाड़ा। जोन हवल जोन गुलाबबागसे हार गया और जोन अमीराकदल ने जोन बटमालू को हरा दिया। तीसरे दिन के अंतिम मैच जोन अमीराकदल और जोन गुलाबबाग के बीच हुये जिसमें अमीराकदल को जीत मिली।

संक्षिप्त समाचार

पोल वॉल्टर डुप्लांटिस ने बुबका का विश्व रिकार्ड तोड़ा

रोम । स्वीडन के पोल वॉल्टर अर्मांड डुप्लांटिस ने सर्जेइ बुबका का 26 साल पुराना आउटडोर विश्व रिकार्ड तोड़ दिया है। डुप्लांटिस ने रोम में गोल्डन गाला पियेत्रो मेनिया मीट में दूसरे प्रयास में छह मीटर 15 सेंटीमीटर की कूद लगाकर बुबका का छह मीटर 14 सेंटीमीटर का रिकार्ड तोड़ा जो उन्होंने जुलाई 1994 में बनाया था। डुप्लांटिस के नाम 6.18 मीटर का इंडोर विश्व रिकार्ड पहले ही से है जो उन्होंने फरवरी में ग्लासगो में बनाया था।

आईपीएल कॉमेंट्री पैनल से हटाए जाने के बाद संजय मांजरेकर ने तोड़ी चुप्पी, दिया यह बयान

स्पोर्ट्स डेस्क । लंबे इंतज़ार के बाद आईपीएल का आयोजन इस साल यूएई में होने जा रहा है। आईपीएल का ओपनिंग मैच चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। मैच के लिए आबुधाबी में सभी तैयारियां की जा रहीं हैं। लेकिन इस बार आईपीएल में दर्शक कमेंटेटर संजय मांजरेकर की कमेंट्री को नहीं सुन पाएंगे। बीसीसीआई ने उन्हें आईपीएल की कमेंट्री पैनल से हटा दिया है। आईपीएल में कॉमेंट्री पैनल में शामिल न करने पर संजय मांजरेकर ने बयान दिया है। संजय मांजेरकर ने कहा कि यह बेहतर है कि मैं उस मुद्दे पर बात न करूं। हमारे देश में किसी खिलाड़ी की आलोचना करना एक संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। दूसरी बात यह है कि हम अंग्रेजी भाषा को समझने में गलती कर देते हैं। अंग्रेजी में कई बार वह मतलब नहीं होता जो हमारे देश समझा जाता है। उन्होंने इसके ही उदाहरण देते हुए कहा कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और कमेंटेटर नासिर हुसैन ने भारतीय टीम को गधा नहीं कहा था उसका मतलब था कि भारतीय टीम में कुछ खिलाड़ी धीमें हैं। बता दें कि मांजेरकर ने ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को लेकर टिप्पणी की थी जिसमें उन्होंने बता दें कि मांजेरकर ने ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को लेकर टिप्पणी की थी जिसमें उन्होंने अंग्रेजी में कहा था कि जडेजा बिट्स एंड पीसीज़ में प्रदर्शन करते हैं। जिस पर खूब विवाद हुआ था और मांजरेकर को काफी आलोचना का भी सामना करना पड़ा था। उन्हे सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार भी होना पड़ा था।

आईपीएल 2020 : प्रत्येक टीम की एक बड़ी खासियत और कमजोरी

अबुधाबी ।

कोरोना वायरस महामारी के बीच यूएई में 19 सितंबर से इंडियन प्रीमियर लीग शुरू जा जाएगी। पहली ही मैच में एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी के शांत रवैये, रोहित शर्मा की कप्तानी पर सभी की नजरें होंगी। आईपीएल पहले भी विदेश में हुआ है लेकिन इस बार करोड़ों डॉलर का यह क्रिकेटिया तमाशा पहली बार जैविक सुरक्षित माहौल में होगा। इसमें क्रिस गेल और डेविड वार्नर के गगनभेदी छक्कों पर तालियां पीटने वाले नहीं होंगे और ना ही सुपर ओवर में कोई शोर सुनाई देगा। इसके बावजूद कोई शिकायत नहीं क्योंकि कम से कम खेल देखने को तो मिलेगा। मुंबई इंडियंस : सबसे मजबूत टीमों में से एक। रोहित के अलावा हार्दिक और कृणाल पंड्या, कीरोन पोलार्ड और 'डैथ ओवरों के शहंशाह' गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं। चेन्नई सुपर किंग्स : टीम को भले ही 'बूढों की फौज' कहें लेकिन इस टीम ने साबित किया है कि सफलता और प्रतिभा उम्र के मोहताज नहीं होते। शेन वाटसन, ड्वेन ब्रावो, फाफ डु प्लेसी और रविंद्र जडेजा ने अपना सौ प्रतिशत इस टीम को दिया है और इस बार भी देंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु : कोहली की उपलब्धियों में आईपीएल खिताब की कमी खटकती है जिसे वह पूरा करना चाहेंगे। आरोन फिंच, क्रिस मौरिस और देवदत्त पडीक्कल की मौजूदगी में टीम मजबूत दिख रही है। दिल्ली कैपिटल्स : पिछले साल लय हासिल की और उनके पास अय्यर जैसा बेहतरीन कप्तान, पृथ्वी साव और ऋषभ पंत जैसे प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं। इसके साथ ही रविचंद्रन अश्विन जैसा अनुभवी गेंदबाज टीम में है। किंग्स इलेवन पंजाब : राहुल की पंजाब टीम का अच्छा प्रदर्शन भविष्य में राहुल को भारतीय टीम के संभावित कप्तानों की जमात में शामिल कर सकता है । यह देखना होगा कि ग्लेन मैक्सवेल, गेल और मोहम्मद शमी जैसे स्टार खिलाड़ियों को वह कैसे संभालते हैं। सनराजइर्स हैदराबाद : कप्तान डेविड वार्नर मैच जिताने के फन में माहिर हैं। उनके पास जॉनी बेयरस्टॉ की आक्रामकता, केन विलियमसन की 'कूलनेस' और राशिद खान की कलाई का जादू है। कोलकाता नाइट राइडसः आईपीएल का कुछ हिस्सा जब 2014 में यूएई में खेला गया था, तो केकेआर ने खिताब जीता था। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हरफनमौला आंद्रे रसेल उनकी टीम में हैं। उन्होंने पिछले सत्र में 52 छक्के जड़े थे। अंडर 19 विश्व कप सितारे शुभमन गिल, शिवम मावी और कमलेश नागरकोटी टीम में युवा जोश भरेंगे जबकि इयोन मोर्गन के रूप में अनुभवी कप्तान टीम के पास है। राजस्थान रॉयल्स : विदेशी खिलाड़ियों जोस बटलर, स्टीव स्मिथ और जोफ्रा आर्चर पर दारमोदार। स्टोक्स अपने बीमार पिता की देखभाल के लिये न्यूजीलैंड में है ।

चैम्पियन शो डाउन शतरंज - जीत की हैट्रिक से कार्लसन नें बनाई बढ़त

सेंट लुईस ,यूएसए ।

चैम्पियन शो डाउन ऑनलाइन सुपर ग्रांड मास्टर रैपिड टूर्नामेंट के दूसरे दिन विश्व चैम्पियन मेगनस कार्लसन जोरदार लय मे नजर आए और लगातार तीन मुकाबले जीतकर पहले स्थान पर पहुँच गए है । मेगनस कार्लसन नें दूसरे दिन हुए तीन मुकाबलों मे पहले सबसे आगे चल रहे अर्मेनिया के लेवोन आरोनियन को सफ़ेद मोहरो से खेलते हुए गुन्फ़ील्ड ओपेनिंग मे 34 चालों मे मात दी तो उसके बाद काले मोहरो से अमेरिका के दोमिंगेज पेरेज को फिलिडर ओपनिंग मे 41 चालों मे हारा दिया । तीसरा मुकाबला था भारत के पेंटाला हरीकृष्णा से और इस बार काले मोहरो से खेल रहे पेंटाला की कारो कान ओपेनिंग कार्लसन के सामने बिखर गयी और उन्हे मात्र 31 चालों मे हार स्वीकार करनी पड़ी । हरीकृष्णा जो कल तक सबसे आगे चल रहे थे उन्हे इससे पहले दिन की शुरुआत मे रूस के इयान नेपोंनियची से भी हार का सामना करना पड़ा था जबकि लेवोन आरोनियन से उन्होने मुकाबला ड्रॉ खेला । दूसरे दिन अंक तालिका मे अमेरिका के वेसली सो नेपोंनियची के साथ बेहतर करते नजर आए । राउंड 6 के बाद मेगनस कार्लसन 9 अंक के साथ पहले ,8 अंक के साथ नेपोंनियची और वेसली सो सयुंक्त दूसरे स्थान पर है ,लेवोन आरोनियन 7 अंक ,हरीकृष्णा 6 अंक , अलेक्ज़ेंडर ग्रीसचुक, जेफ्री जियांग और हिकारु नाकामुरा 5 अंक ,दोमिंगेज पेरेज 4 अंक तो अलीरेजा फिरौजा 3 अंक बनाकर खेल रहे है, अब अंतिम दिन 3 राउंड और खेले जाएँगे ।

डीजे ब्रावो के पास बड़ा मौका, अश्विन का यह रिकॉर्ड तोडने की दहलीज पर

नई दिल्ली । चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराऊंडर डीजे ब्रावो जब आईपीएल 2020 में उतरेंगे तो उनके पास सीएसके के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का एक बड़ा रिकॉर्ड तोडने का मौका होगा। ब्रावो लंबे समय से धोनी की कप्तानी वाली सीएसके टीम से जुड़े हुए हैं। वह न सिर्फ गेंद से बल्कि बल्ले से भी अहम पारियां खेलने के लिए जाने जाते हैं। अब वह सीएसके की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अश्विन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। ब्रावो के नाम अभी 103 मैचों में 118 विकेट दर्ज हैं। वहीं, अश्विन ने 121 मैचों में 120 विकेट चटकाए थे। उम्मीद है कि ब्रावो आगामी कुछेक मैचों में ही अश्विन का यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। बता दें कि ब्रावो का आईपीएल करियर बेहद शानदार रहा है। उन्होंने 134 मैचों में 1483 रन तो बनाए हैं साथ ही साथ 147 विकेट भी निकाले हैं। ब्रावो की औसत 24.61 रही है। बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग 2020 19 सितंबर से शुरू होने वाला है।

आईपीएल 2020 : टीम ऐंथम सान्ग पर ट्रोल हुई आरसीबी टीम, फैंस ने किए ये मजेदार ट्वीट्स

स्पोर्ट्स डेस्क ।

आईपीएल का रंगमंच पूरी तरह सज चुका है और कल यानि के 19 सितंबर से इसका आगाज़ हो रहा है। आईपीएल का पहला मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में अबुधाबी के शेख जाएद स्टेडियम में खेला जाएगा। सभी टीमें आईपीएल के लिए तैयार हो गई हैं। इसी बीच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपनी टीम का ऐंथम सान्ग रिलीज़ किया जो आरसीबी के फैंस को ज़रा भी पसंद नहीं आया और फैंस ने इस ऐंथम सान्ग को ट्रोल करना शुरू कर दिया। आरसीबी टीम के ऐंथम सान्ग प्ले बोल्ड जैसे ही रिलीज़ किया आरसीबी के फैंस ने इसे ट्रोल करना शुरू कर दिया। फैंस ने लिखा कि एक तरफ हम अपनी मातृ भाषा को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहें हैं दूसरी ओर आप टीम के गाने को हिंदी और इंग्लिश में गा रहें हैं। वहीं एक अन्य यूज़र ने लिखा कि बाकी कि टीमें सीएसके और पंजाब अपनी मातृ भाषा में ही ऐंथम सान्ग गा रहें हैं और आप हिंदी और इंग्लिश में गाने को रिलीज़ कर रहें हैं। बेहतर होता कि आप कन्नड़ में गाने को रिलीज़ करते। गौर हो कि आरसीबी कि टीम एक बार भी आईपीएल का खिताब नहीं जीत पाई है लेकिन फैंस हमेशा ही इस टीम को सपोर्ट करने स्टेडियम में पहुंच जाते हैं । आरसीबी की टीम तीन बार 2009,2011 और 2016 में आईपीएल के फाइनल में पहुंची है लेकिन एक बार भी खिताब को अपने कब्जे में नहीं ले पाई है। हालांकि आरसीबी के कप्तान विराट कोहली का मानना है कि उनकी टीम इस बार पहले के मुकाबले कहीं बेहतर हैं और टीम का संतुलन भी काफी बढ़िया है।

रविचंद्रन अश्विन ने शेयर की कैटरीना कैफ की फोटो, रमेश पोवार को कर दिया टैग

नई दिल्ली । आई.पी.एल. 2020 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले रविचंद्रन अश्विन बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ की फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के चलते चर्चा में आ गए हैं। दरअसल, कैफ को उनके एक फैन ने एक मीम बनाकर भेजा था जिसमें अश्विन, रमेश पोवार, ग्रीम स्वान और कैटरीना कैफ की फोटो लगी हुई थी। उक्त फोटो में सभी के हाथ बॉलिंग करने वाले अंदाज में दिख रहे हैं। अश्विन ने इसे शेयर करते हुए लिखा है- हा हा हो... रामेश पोवार, ग्रीम स्वान। बता दें कि अश्विन टीम इंडिया के प्रमुख स्पिन गेंदबाज हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड प्रदर्शन कर 300 विकेट हासिल की हैं। इसके अलावा आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। उन्होंने 139 मैचों में 125 विकेट हासिल की हैं। इस दौरान उनका इकोनमी 26.43 और इकोनमी रेट 6.79 रहा है। अश्विन बीते साल किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेलते हुए मांकड़िंग नियम अपनाने के कारण विवाद में आ गए थे। उन्होंने राजस्थान के खिलाफ अहम मैच में नॉन स्ट्राइकर क्रीज से बाहर जा रहे बटलर को आऊट किया था। इसके बाद अश्विन पर दबाव बनने लगा कि वह मांकड़िंग का इस्तेमाल करें। लेकिन अश्विन ने तर्क दिया कि क्रिकेट में इसको लेकर नियम ही नहीं है। इस मामले में उनकी दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पोंटिंग के साथ हुई बयानबाजी भी चर्चा में आई थी।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

3 कृषि विधेयक, सरकार बता रही बड़ा कदम और किसान कर रहे विरोध

नेशनल डेस्क।

कृषि संबंधित बिल को लेकर इन दिनों संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। जहां किसान सड़कों पर आ गएहैं वहीं विपक्ष सरकार का विरोध कर रहे हैं। कृषि विधेयक के विरोध में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हरसिमरत के इस्तीफे के बाद कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। केंद्र सरकार तीन कृषि विधेयकों को कृषि सुधार में अहम कदम बता रही है। मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता बिल। केंद्रीय कैबिनेट पहले ही इनसे जुड़े अध्यादेश पास कर चुकी है, जिन्हें अब संसद में बिल के रूप में पेश किया गया है। लोकसभा से मंगलवार को आवश्यक वस्तु से जुड़े संशोधन बिल पास हो गया है। ये विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे। उन्होंने कहा कि इस कृषि सुधार से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए-नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनका मुनाफा बढ़ेगा। इससे हमारे कृषि क्षेत्र को जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, वहीं अन्नदाता सशक्त होंगे। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक एक इको-सिस्टम बनाएगा। इससे किसानों को अपनी पसंद के अनुसार उपज की बिक्री-खरीद की स्वतंत्रता होगी। किसानों के पास फसल बेचने के लिए वैकल्पिक चैनल उपलब्ध होगा जिससे उनको उपज का लाभकारी मूल्य मिल पाएगा। पहले व्यापारी फसलों को किसानों के औने-पौने दामों में खरीदकर उसका भंडारण कर लेते थे और कालाबाजारी करते थे, उसको रोकने के लिए 1955 बनाया गया था जिसके तहत व्यापारियों द्वारा कृषि उत्पादों के एक लिमिट से अधिक भंडारण पर रोक लगा दी गई थी। कृषि संबंधी तीन विधेयकों से नाराज किसान बीते दिनों से देश के अलग-अगल हिस्सों में प्रदर्शन किए हैं। पंजाब और हरियाणा में कई जगह हाइवे जाम कर दिए गए। दोनों राज्यों के किसानों ने विधेयक के खिलाफ नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी धरना दिया। भारतीय किसान यूनियन (लाखोवाल) के महासचिव हरिंदर सिंह लाखोवाल ने कहा कि जो सांसद संसद में कृषि विधेयकों का समर्थन करेंगे, उन्हें गांवों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। दरअसल किसानों को डर है कि नए कानून के बाद एमएसपी पर खरीद नहीं होगी। विधेयक में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि मंडी के बाहर जो खरीद होगी वह एमएसपी से नीचे के भाव पर नहीं होगी। चूंकि बाहर बेचने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, ऐसे में किसानों को फायदा मिल सकता है। हालांकि अगर बाहर दाम कम मिलते हैं तो किसान मंडी आकर फसल बेच सकते हैं जहां उन्हें एमएसपी मिलेगा।

संक्षिप्त समाचार

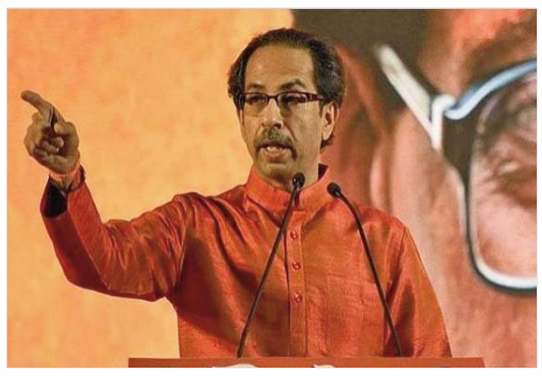

शिवसेना ने आर्थिक संकट के लिए केंद्र सरकार को लिया आड़े हाथों

मुंबई। शिवसेना ने देश में जारी आर्थिक संकट के लिए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए शुक्रवार को कहा कि नोटबंदी और कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए लॉकडाउन को गलत तरीके से लागू करने के कारण मौजूदा हालात पैदा हुए हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रकाशित एक संपादकीय में केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा गया है, 13 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि देश में स्वास्थ्य संबंधी कोई आपातकाल नहीं है, जबकि 22 मार्च को प्रधानमंत्री ने एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाया और 24 मार्च को सिर्फ चार घंटे की नोटिस पर 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की। भाजपा की पूर्व सहयोगी पार्टी ने कहा कि उस दिन शुरु हुई अव्यवस्था और अनिश्चितता आज भी जारी है। संपादकीय में कहा गया कि यह वक्त की मांग है कि केंद्र इस संकट के दौरान राज्यों के साथ मजबूती से खड़ा रहे। संपादकीय में कहा गया कि केंद्र के खजाने में कम से कम 22 प्रतिशत राजस्व मुंबई से आता है, लेकिन केंद्र राज्यों की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अखबार ने कहा कि केंद्र ने लॉकडाउन के दौरान 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की, लेकिन यह एक रहस्य है कि यह राशि कहां गई।

गाय के ऊपर कांग्रेस प्रत्याशी का चुनाव प्रचार, बीजेपी ने की कार्रवाई की मांग

इंदौर । मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा चुनाव प्रचार का अनोखा तरीका अपनाया गया है। जिसमें एक गाय का सहारा लेकर प्रचार किया जा रहा है। जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गाय के शरीर पर वोट मांगने के लिए सांवेर से कांग्रेस उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डु का नाम लिखा हुआ है। इसे लेकर बीजेपी पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की तैयारी में हैं, तो वही कांग्रेस ने इसे ग्रामीणों द्वारा किया जाना बताया है। दरअसल, विधानसभा की सबसे हॉट सीट इंदौर की सांवेर सबसे ज्यादा चर्चित है। वहीं जहां से एक गाय की तस्वीर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें गाय के ऊपर कांग्रेस उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डु का नाम लिखा हुआ है। साथ ही कांग्रेस का चुनाव चिह्न भी छपा हुआ है। गाय सड़क पर खड़ी है। हालांकि यह किसकी शरारत है अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाया है। वहीं बीजेपी ने इसे पशु क्रूरता अधिनियम के तहत शिकायत करने की बात कही है। गौरतलब है कि एमपी विधानसभा उपचुनाव में सांवेर सबसे हॉट सीट है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सीट पर बीजेपी की तरफ से जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट चुनाव लड़ेंगे।

पत्नी को फोन पर कहा- मैं कोरोना पॉजिटिव हूं, और मरने वाला हूं, गायब होने के बाद मिला गर्लफ्रेंड के पास

नई दिल्ली। भारत में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोविड-19 के 96,424 नये मरीज सामने आने के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 52 लाख के पार हो गई है। कोरोना वायरस से संक्रमत कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 52,14,677 हो गई है जबकि गत 24 घंटे में 1,174 और लोगों की मौत के साथ अबतक इस महामारी में 84,372 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं नवी मुंबई के वाशी में हैरान कर देने वाला मामला देखने को मिला जहां पत्नी को कोरोना पॉजिटिव का कहकर गायब हुआ पति गर्लफ्रेंड के पास पाया गया। दरअसल 24 जुलाई की रात 28 साल के व्यक्ति ने अपनी पत्नी को फोन कर बताया, मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है मैं अब जी नही सकता। पत्नी कुछ समझ पाती इसके पहले ही पति का फोन बंद हो गया। घबराई पत्नी ने तुंरत गुम होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराते हुए कहा कि उसके पति ने 24 जुलाई की रात उसको फोन कर कहा कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है मैं अब जी नही सकता। वह कुछ समझ पाती इसके पहले ही पति का फोन बंद हो गया। जांच में जुटी पुलिस को व्यक्ति के प्रेम प्रसंग की जानकारी मिली और फिर जांच की दिशा बदलते हुए पुलिस ने नये सिरे से तलाश शुरू की और महीने भर की मशक्कत के बाद उसके इंदौर में होने का पता चला। एक टीम इंदौर जब पहुंची तो व्यक्ति वहां अपनी प्रेमिका के साथ पाया गया। 15 सितंबर को पुलिस उसे पकड़कर नवी मुंबई लाई।

कृषि अध्यादेश के विरोध में अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने केंद्रीय मंत्री पद से दिया इस्तीफा

नई दिल्ली। शिरोमणि अकाली दल की नेता और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने संसद में पेश किये गये कृषि से संबंधित दो विधेयकों के विरोध में बृहस्पतिवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ट्वीट किया, ''मैंने किसान विरोधी अध्यादेशों और विधेयकों के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। किसानों की बेटी और बहन के तौर पर उनके साथ खड़े होने पर गर्व है। इससे पहले शिरोमणि अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल ने लोकसभा में कहा कि पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल संसद में लाये गये कृषि संबंधी विधेयकों के विरोध में केंद्र सरकार से इस्तीफा देंगी। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2020 और कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 पर चर्चा में भाग लेते हुए सुखबीर बादल ने कहा, ''शिरोमणि अकाली दल किसानों की पार्टी है और वह कृषि संबंधी इन विधेयकों का विरोध करती है। विधेयक का पुरजोर विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों ने अन्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अकाली दल नेता ने लोकसभा में कहा, '' मैं एक घोषणा करना चाहता हूं कि हमारी मंत्री हरसिमरत कौर बादल मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगी। उन्होंने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि उनकी पार्टी ने प्रारंभ में इन अध्यादेशों का समर्थन किया था। सुखबीर बादल ने कहा कि हरसिमरत कौर बादल ने मंत्रिमंडल की बैठक में चिंता प्रकट की थी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर प्रस्तावित कानून की खामियों को रेखांकित किया था। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि इस पार्टी का इस मुद्दे पर दोहरा मानदंड है और 2019 के लोकसभा चुनाव तथा 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में उसके घोषणा पत्र में एपीएमसी अधिनियम को खत्म करने का उल्लेख था। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष ने कहा कि इन विधेयकों का पंजाब के 20 लाख किसानों और कृषि क्षेत्र के 15-20 लाख मजदूरों पर प्रभाव पड़ेगा।

केजरीवाल की विपक्षी पार्टियों को नसीहत- वॉकआउट का ड्रामा छोड़ अन्नदाताओं का दो साथ

नेशनल डेस्क।

कृषि से संबंधित तीन विधेयकों करो लेकर आप के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जंग छेड़ दी है। अब उन्होंने इस जंग में सभी विपक्षी पार्टियों से एकजुट होने की अपील की है। केजरीवाल ने सांसदों से कहा कि देश के किसान उन्हे देख रहे हैं, ड्रामा करने की बजाय बिल का विरोध करें। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को ट्वीट में लिखा कि केंद्र के तीनों विधेयक किसानों को बड़ी कंपनियों के हाथों शोषण के लिए छोड़ देंगे। मेरी सभी गैर भाजपा पार्टियों से बिनती है कि राज्यसभा में एकजुट होकर इन विधेयकों का विरोध करें, सुनिश्चित करें कि आपके सभी स्क्क मौजूद हों और वॉकआउट का ड्रामा ना करें। पूरे देश के किसान आपको देख रहे हैं। दरअसल केजरीवाल ने कृषि से संबंधित तीन विधेयकों को ''किसान-विरोधी बताते हुए वीरवार को केंद्र से इन्हें वापस लेने की मांग की थी। केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि खेती और किसानों से संबंधित तीन विधेयक संसद में लाए गए हैं जो किसान विरोधी हैं। देश भर में किसान इनका विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार को इन तीनों विधेयकों को वापस लेना चाहिए। आम आदमी पार्टी संसद में इनके विरोध में वोट करेगी।

देखें उन राज्यों की लिस्ट जहां 21 सितंबर से खुल रहे स्कूल

नेशनल डेस्क। कोरोना संकट के बीच देश धीरे-धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। मंदिर, मॉल और रेस्त्रां आदि खुल गए हैं। ऐसे में अब स्कूल कब खुलेंगे यह सवाल हर किसी के मन में हैं। केंद्र सरकार के अनलॉक 4 के ऐलान किए जाने के बाद से कुछ राज्यों ने अपने यहां 21 सितंबर से स्कूल खोलने की घोषणा की है। अभी 9 से 12वीं की कक्षाएं लगाई जा रही हैं। हालात सामान्य रहे तो शेष कक्षाएं शुरू करने पर विचार होगा। आंध्र प्रदेश में 21 सितंबर से स्कूल खोले जा रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य सरकार के हालिया निर्देश के अनुसार, 50 प्रतिशत टीचिंग और 50 प्रतिशत नॉन टीचिंग स्टाफ कर्मचारियों को स्कूल जाने की अनुमति दी गई है। अनलॉक 4.0 दिशानिर्देशों के अनुसार, छात्रों को अपने अभिभावकों से लिखित सहमति के बाद स्कूल आने की अनुमति दी जाएगी। झारखंड सरकार भी महामारी के बीच स्कूल खोलने के पक्ष में है। झारखंड के शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ महतो ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि एक सर्वे से हमें पता चला है कि शहरी क्षेत्रों में ऑनलाइन क्लास का महज 27 फीसदी छात्र ही लाभ ले पा रहे हैं। राज्य सरकार ने कक्षा 10 और 12वीं के छात्रों के लिए 21 सितंबर से स्कूलों को फिर से खोलने की योजना बनाई है।

बाइक हादसे में गई थी विंग कमांडर की जान; बुजुर्ग मां ने हार्ले-डेविडसन से मांगा 1.95 करोड़ मुआवजा

नई दिल्ली। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर सुनील अग्निहोत्री की 80 वर्षीय बुजुर्ग मां गायत्री देवी ने मोटरसाइकिल कंपनी हार्ले-डेविडसन के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में 1.95 करोड़ का मुकदमा दायर किया है। गायत्री देवी का आरोप है कि हार्ले-डेविडसन की बाइक के दोषपूर्ण ब्रेकिंग डिजाइन के कारण उन्होंने अपना बेटा और वायु सेना ने एक अफसर खोया है। गायत्री देवी के वाद पर पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने हार्ले-डेविडसन को समन जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के हाथरस निवासी गायत्री देवी ने अधिवक्ता पुष्पेंद्र ढाका के माध्यम से पटियाला हाउस कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। पुष्पेंद्र ढाका ने बताया कि मार्च 2014 में पायलट सुनील ने गुरुग्राम स्थित हार्ले-डेविडसन के शोरूम से 41 लाख कीमत की एक्सजी-750 स्ट्रीट-750 मॉडल की बाइक खरीदी थी। वर्ष 2017 में हिमाचल प्रदेश के कसौली स्थित एयर फोर्स स्टेशन पर तैनाती के दौरान सुनील 19 मार्च 2017 को बाइक का फ्यूल-कैप ठीक कराने के लिए शहर में जा रहे थे।

किसान संबंधी विधेयकों के लोकर राज्यों से परामर्श नहीं किया गया : चिदंबरम

नई दिल्ली।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने लोकसभा में किसान संबंधी दो विधेयकोंअनुमोदित करने को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसानों के विरोध प्रदर्शन पर शुक्रवार को कहा कि यह जनता और सरकार के बीच की दूरी को प्रदर्शित करता है और यह दर्शाता है कि राज्यों से परामर्श नहीं किया गया है। चिदंबरम ने आज.कई ट्वीट किये।उन्होंने कहा कि किसान संबंधी दो विधेयकों को लोकसभा ने अनुमोदित कर दिया है। पंजाब और हरियाणा के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।यह जनता और सरकार के बीच की दूरी को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस नेता ने कहा,दोनों विधेयक हमारे अपूर्ण खाद्य सुरक्षा प्रणाली के तीन स्तंभों को चुनौती देते हैं। वे हैं , न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), सार्वजनिक खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.)। उन्होंने कहा ,तमिलनाडु में किसानों ने मुझे बताया कि वे 1150 रुपये के एमएसपी के मुकाबले निजी व्यापारियों को 850 रुपये में धान बेच रहे हैं। राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करना होगा। उन्होंने कहा कि विधेयकों में गंभीर दोष यह है कि वे यह निर्धारित नहीं करते हैं कि किसान को जो कीमत मिलेगी वो एमएसपी से कम नहीं होगी। राज्यों से परामर्श नहीं किया गया। भाजपा सरकार द्वारा यह कानून पारित करना राज्यों के अधिकार और संघवाद लिए एक बड़ा झटका है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर हो रहे विरोध पर गुरुवार को इन्हें ऐतिहासिक बताते हुए कहा था कि किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी तथा अन्नदाता सशक्त होंगे। कृषि से जुड़े विधेयकों के विरोध में मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री अकाली दल बादल प्रतिनिधि हरसिमरत कौर बादल ने कल इस्तीफा दे दिया था ।

राज्यसभा से होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 पास

नेशनल डेस्क। होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा से पारित हो गया है। इसके साथ ही भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 को भी पास कर दिया गया है। संशोधनों के माध्यम से होम्योपैथी शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक नियामक सुधार सुनिश्चित होंगे और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए पारदर्शिता एवं जवाबदेही तय की जाएगी। इस बिल के पास होने से अब होम्योपैथी के छात्रों को गुणवत्ता के साथ-साथ सस्ती पढ़ाई मुहैया कराई जा सकेगी। इस बिल में होम्योपैथी से संबंधित उच्च स्तरीय विशेषज्ञों की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराई जा सकेगी। इसके साथ ही आयोग देश के सभी हिस्सों में किफायती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ावा देगा। केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के स्थान पर राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन किया जा सकेगा। दरअसल राज्यसभा में शुक्रवार को कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने सरकार से सवाल किया कि होमियोपैथी केंद्रीय परिषद के गठन में तीन साल क्यों लग गए। कांग्रेस सदस्य रिपुन बोरा ने कहा कि होमियोपैथी केंद्रीय परिषद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उसके स्थान पर संचालक मंडल की स्थापना की गयी थी। शुरू में कहा गया था कि एक साल के अंदर परिषद का गठन कर लिया जाएगा। बाद में वह समय बढ़ाकर दो साल कर दिया। बोरा सदन में होमियोपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020 और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020 पर एक साथ हुयी चर्चा में भाग ले रहे थे।

कंगना की खुली चुनौती- मुझे लड़ाकू साबित कर दिया तो छोड़ दूंगी ट्विटर

नेशनल डेस्क।

सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में चल रही है। वह सोशल मीडिया को हथियार की तरह इस्तेमाल कर अपने आलोचकों पर जमकर वार कर रही हैं। अब इस बीच उन्होंने कहा कि वह लड़ाकू नहीं हैं अगर कोई यह साबित कर देता है कि वह तुरंत ही ट्विटर छोड़ देंगी। कंगना ने वीरवार रात ट्वीट कर लिखा कि मैं भले ही लड़ाकू व्यक्ति लगूं लेकिन यह सच नहीं है, मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने कभी लड़ाई शुरू नहीं की, अगर कोई मुझे गलत साबित कर दे तो ट्विटर छोड़ दूंगी। उन्होंने लिखा कि मैं कभी खुद झगड़ा शुरू नहीं करती बस हर लड़ाई खत्म करती हूं। भगवान कृष्ण ने कहा था अगर कोई झगड़ने आए तो उसे न नहीं कहना चाहिए। बता दें कि ने कंगना के 48 करोड़ की कीमत वाले दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया जिसके बाद

से वह शिवसेना के खिलाफ जमकर बोल रही है। इससे पहले भी उन्होंने लिखा था कि मैं एक क्षत्राणी हूं, सर कटा सकती हूं लेकिन सर झुका सकती नहीं। इस पर अनुराग कश्यप ने जवाब दिया था, बस एक तू ही है बहन- इकलौती मणिकर्णिका।

युवाओं के सामने झुकी योगी सरकार, सभी विभागों में शीघ्र भर्ती पूरा करने का दिया निर्देश

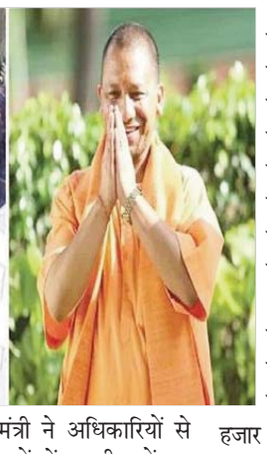

लखनऊ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को 'बेरोजगारी दिवस' के रूप में मनाना युवाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में नौकरियों को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से सभी विभागों में खाली पदों का ब्यौरा मांगा है। इसके साथ ही अगले 3 महीनों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करते हुए 6 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र बांटने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने लोकभवन में बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि अब तक हुई 3 लाख भर्तियों हो चुकी है। पारदर्शी तरीके से अगले तीन महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू करें। छह महीने के अंदर नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार यूपी लोक सेवा आयोग से पारदर्शी और निष्पक्ष भर्तियां हुई हैं। उसी प्रकार तेजी से भर्तियां की जाएं। अब तक हुई बड़ी सरकारी भर्तियों में एक लाख 37 हजार पुलिस की भर्ती हो चुकी है। 50 हजार टीचर की भर्ती हो चुकी है। सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक शिशिर ने जानाकारी देते हुए बताया कि 21 सितंबर को सीएम सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों के प्रमुखों के साथ भी बैठक करेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक शिशिर ने जानाकारी देते हुए बताया कि 21 सितंबर को सीएम सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों के प्रमुखों के साथ भी बैठक करेंगे। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा, 'सभी विभागों में रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए विभागों को रिक्तियों के आंकड़े कल तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। चयन प्रक्रिया में शुचिता और पारदर्शिता हमारी नीति है और इसे प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाएगा।'' एक अन्य ट्वीट में योगी ने कहा, ''हमारे युवा साथियों में प्रतिभा है, क्षमता है, मेधा है। वर्तमान सरकार सभी को बिना भेदभाव के समान अवसर उपलब्ध करा रही है। सभी विभागों में रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होगी। हमारा प्रयास है कि आगामी 6 माह में सभी विभागों में चयन प्रक्रिया को संपन्न करा लिया जाए।''

पारूल साहू के कांग्रेस में शामिल होने पर नरोत्तम मिश्रा का तंज, बोले- कांग्रेस में व्यक्तियों का टोट

भोपाल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सुरखी विधानसभा की पूर्व विधायक के कांग्रेस में शामिल होने पर बड़ा हमला किया है। गृहमंत्री ने कहा कि कांग्रेस में व्यक्तियों का टोटा है। इसलिए वह प्रत्याशी ढूंढ रही है। पिछली जो सूची आई है उसमें बमोरी से लेकर भांडेर और ग्वालियर तक सब आयातित लोग ही है। जैसे कांग्रेस की स्थिति है वैसे ही पार्टी में आने वालों की स्थिति है। गृहमंत्री ने पूर्व सीएम कमलनाथ के ग्वालियर दौरे को लेकर कहा अच्छा है स्वागत है। उनका आए, लेकिन जब मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं आए, हमारे सवालों का कांग्रेस कभी भी जवाब नहीं दे पाएगी क्योंकि हम सत्य बात पूछते हैं। उन्होंने किसानों को लेकर कहा- कांग्रेस के समय में किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि कांग्रेस किसान विरोधी थी। राजनीति करना है सीधे-सीधे राजनीति करें। इमरती देवी के बयान को लेकर कहा अब इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत है। हमारे नेता चाहे तो बिल्कुल डिप्टी ष्टरू बना सकते है और जिन लोगों का इमरती जी नाम ले रही है। उन्हें डिप्टी ष्टरू बनाने में वह सभी सक्षम हैं। गृहमंत्री ने मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कहा लगातार काम करना ही गरीब की सही सेवा कहलाती है। कांग्रेस के पिछले 15 महीने से ज्यादा काम इन 7 दिनों में कर दिए गए है। कांग्रेस के बेरोजगारी दिवस मनाने को लेकर कहा कि सही बात है कांग्रेस ने सही किया बेरोजगार दिवस मनाया, क्योंकि उन्होंने एक भी रोजगार नहीं दिया था। पिछले 15 महीनों में एक भी बेरोजगार व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी किसानों को धोखा देने वाली पार्टी है कांग्रेस। विधानसभा के सत्र को लेकर कहा हमारे विधायक लगातार कोरोना पॉजिटिव होते जा रहे हैं। इसलिए सर्वदलीय बैठक में भी आम राय यही आई थी ।

क्रांति समय

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

ट्रंप का दावा- चीन से पहले अक्टूबर में ही अमेरिकी जनता को मिलेगी कोरोना वैक्सीन

वाशिंगटन।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि देश के नागरिकों को अक्टूबर में ही कोरोना वैक्सीन मिलने लगेगी। चीन ने एक दिन पहले ऐलान किया था कि नवंबर के पहले हफ्ते से आम लोगों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाएगी। अब ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में अक्टूबर में कोरोना वैक्सीन का वितरण शुरू हो सकता है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में वैक्सीन अक्टूबर से वितरित की जा सकती है और 2020 के अंत तक वैक्सीन की करीब सौ करोड़ (1 अरब) खुराक वितरित की जा सकती हैं। ट्रंप ने यहां संवाददाताओं से कहा कि हम बहुत सुरक्षित और प्रभावी तरीके से वैक्सीन को वितरित करने और वितरित करने के लिए ट्रैक पर हैं। हमें लगता है कि हम अक्टूबर में कभी भी शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम अक्टूबर के मध्य में वितरण शुरू कर पाएंगे इसमें शायद थोड़ी देर हो लेकिन ये इसी महीने में होगा। उन्होंने कहा कि कुछ ही महीनों में कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा। उधर अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के निदेशक रॉबर्ट रेडफ़ील्ड के यह कहने के बावजूद कि कोरोना वायरस के समय टीके की तुलना में मास्क पहनना अधिक प्रभावी होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी राय रखते हुए कह दिया कि मास्क वैक्सीन से अधिक प्रभावी नहीं है। बता दें कि रेडफील्ड ने एक सार्वजनिक बातचीत में कहा था, मैं यहां तक कह सकता हूं कि जब मैं वैक्सीन लूंगा तो 70 से अधिक प्रतिशत की तुलना में यह फेस मास्क से मुझे सुरक्षा प्रदान करने की अधिक गारंटी देता है। और अगर मुझे प्रतिरक्षा नहीं मिलती है, तो टीका मेरी रक्षा करने वाला नहीं है। यह फेस मास्क करेगा। इस पर ट्रंप ने कहा, यह वैक्सीन की तुलना में किसी भी तरह से अधिक प्रभावी नहीं है। यदि आप उनसे पूछेंगे, तो वह कहेंगे कि वह इस सवाल को नहीं समझा।

गलवान की हिंसक झड़प में मारे गए थे कई चीनी सैनिक, 3 महीने बाद चीन ने किया स्वीकार

नेशनल डेस्क।

लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के 3 महीने बाद चीन ने मान ही लिया कि इस घटना में उसे भी भारी नुक्सान हुआ है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस बात पुष्टि की है कि गलवान में हुई हिंसा में चीनी सैनिकों की भी मौत हुई थी। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ हू झिजिन ने ट्वीट कर लिखा कि जहां तक मुझे जानकारी है कि गलवान घाटी में भारत और चीन सेना के बीच हुई झड़प में चीनी सैनिकों के मारे जाने का आंकड़ा भारत के 20 जवानों से कम था। झिजिन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए यह खुलासा किया। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर का यह भी कहना है कि कोई भी चीनी सैनिक भारत ने बंदी नहीं बनाया था, बल्कि चीन ने भारत के सैनिकों को बंदी बनाया था। झिजिन ने दावा किया कि संघर्ष के दौरान कुछ भारतीय सैनिक भाग गए और कुछ ने आत मसमर्पण कर दिया। इतना ही नहीं ग्लोबल टाइम्स के एडिटर के अनुसार पैंगोंग झील इलाके में भी चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को ऊंचाई वाले इलाकों से हटा दिया है और उन्होंने गतिरोध वाली कई जगहों पर बढ़त हासिल कर ली है। गौरतलब है कि 15 जून की की रात को गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारतीय सेना के कर्नल संतोष बाबू समेत 20 जवान शहीद हो गए थे। सूत्रों के मुताबिक इस झड़प में चीन के करीब 40 जवान मारे गए थे, हालांकि चीन ने अपने जवानों के मारे जाने का कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया था। वह इस बात से इंकार करता रहा कि इस घटना में उसे भी कुछ नुक्सान हुआ है।

गिलगित-बाल्टिस्तान को पूर्ण प्रांत का दर्जा देगा पाकिस्तान, मिलेंगे संवैधानिक अधिकार

इस्लामाबाद।

पाकिस्तान ने गिलगित-बाल्टिस्तान के दर्जे को बढ़ाकर इसे एक पूर्ण प्रांत बनाने का फैसला किया है। पाकिस्तान के मीडिया में बृहस्पतिवार को एक वरिष्ठ मंत्री के हवाले से दी गई रिपोर्ट में यह बात कही गयी। भारत पहले ही पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में यह बता चुका है कि केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर, लद्दाख समेत गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में ठोस बदलाव करने के इस्लामाबाद के प्रयासों का विरोध करते हुए मई में भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पाकिस्तान की सरकार या न्यायपालिका का गैर कानूनी तरीके से कब्जाए गए इन इलाकों पर कोई अधिकार नहीं है। इसमें कहा था कि भारत इस तरह की कार्रवाई को और भारत के जम्मू-कश्मीर के पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए इलाकों में ठोस बदलाव करने के प्रयासों को पूरी तरह से खारिज करता है। बल्कि पाकिस्तान को गैर कानूनी तरीके से कब्जाए इन इलाकों को तुरंत खाली कर देना चाहिए। क्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक कश्मीर एवं गिलगित-बाल्टिस्तान के मामलों के मंत्री अली अमीन गंडापुर ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान जल्द ही क्षेत्र का दौरा करेंगे और गिलगित-बाल्टिस्तान को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने की औपचारिक घोषणा करेंगे जिसके तहत प्रांत को सभी संवैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे। गंडापुर ने कहा कि गिलगित-बाल्टिस्तान को नेशनल एसेंबली और सीनेट समेत सभी संवैधानिक संस्थाओं में पर्याप्त नुमाइंदगी दी जाएगी। मंत्री ने संवाददाताओं से कहा, ''सभी पक्षकारों से विचार-विमर्श के बाद संघीय सरकार ने गिलगित-बाल्टिस्तान को संवैधानिक अधिकार देने पर सैद्धांतिक सहमति जताई है।

नाइजीरिया के एक राज्य में दुष्कर्मियों को बनाया जाएगा नपुंसक, कानून को मंजूरी

लागोस।

नाइजीरिया के कदूना राज्य के गर्वनर ने एक कानून पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत दुष्कर्म के दोषी करार दिए गए व्यक्ति को सर्जरी कर नपुसंक बना दिया जाएगा और 14 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा। गर्वनर नासिर अहमद अल रूफाई ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई से बच्चों को जघन्य अपराध से बचाने में मदद मिलेगी। कोरोना वायरस महामारी के दौरान नाइजीरिया में दुष्कर्म के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। महिला संगठनों ने दुष्कर्मियों के खिलाफ मृत्युदंड समेत कठोर कार्रवाई का अनुरोध किया था। अफ्रीका की सबसे घनी आबादी वाले देश नाइजीरिया में दुष्कर्म के अपराध को रोकने के लिए कदूना राज्य में सबसे कठोर कानून बनाया गया है। राज्य में हाल में संशोधित दंड संहिता में कहा गया है कि 14 साल से अधिक उम्र की लड़कियों, महिलाओं से दुष्कर्म करने वालों को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। पूर्व के कानून में वयस्कों से दुष्कर्म करने पर 21 साल जेल की सजा और बच्चियों से दुष्कर्म के लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान था।

टिकटॉक के बारे में फैसला लेने पर काम जारी: ट्रंप

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने चीन की वीडियो शेयर करने वाली सोशल नेटवर्किंग सेवा टिकटॉक के बारे में फैसला करने के लिए वालमार्ट और ओरेकल के दल के साथ बातचीत की है। पिछले महीने ट्रंप ने टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत यदि दोनों चीनी कंपनियां अपना स्वामित्व किसी अमेरिकी कंपनी को देकर प्रतिबंध से बच सकती हैं। इस समय टिकटॉक का स्वामित्व बीजिंग स्थित बाइटडांस के पास है। शुरुआत में टिकटॉक के साथ बातचीत में माइक्रोसॉफ्ट शामिल था, हालांकि अब ओरेकल और वॉलमार्ट ने इस संबंध में बाइटडांस के साथ बातचीत कर रहे हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, हम एक फैसला कर रहे हैं। हमने आज वॉलमार्ट, ओरेकल से बात की, मुझे लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट अभी भी शामिल है। हम निर्णय लेंगे। लेकिन बहुत कुछ नहीं बदला है। हम जल्द ही निर्णय लेंगे। इस बीच अमेरिकी सांसद टेड क्रूज, जो संसद की विदेश संबंध और न्यायपालिका से जुड़ी समितियों के एक सदस्य भी हैं, ने वित्त मंत्री स्टीवन म्नुचिन को पत्र लिखकर चिंता जताई है कि ओरेकल-टिकटॉक सौदे से अमेरिकी जनता चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव में आ सकती है ।

बीवी को तलाक दे सास से की शादी, ब्रिटेन के 500 साल पुराने कानून को पलट कर दी गई मंजूरी

लंदन ।

यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तलाक देकर अपनी सास से शादी कर ली है। इसके लिए ब्रिटेन के 500 साल पुराने कानून को पलटा गया है। क्लाइव ब्लडेन (65) और ब्रेंडा (77) करीब 30 साल से एक दूसरे के साथ हैं। क्लाइव अपनी पत्नी को छोड़कर सास के साथ रहने लगा था और 1997 में दोनों ने अपनी शादी की घोषणा की तो क्लाइव को गिरफ्तार कर लिया गया था। ब्रिटेन का 500 साल पुराना परिवार नैतिकता कानून जो अभिभावक और बच्चों के बीच यौन संबंध को अपराध मानता है के तहत उसे सात साल की सजा हुई।

इस कानून को बदलने की याचिका दी मगर यूरोपीयन कोर्ट ने 2005 में उसकी सजा बढ़ाकर 10 साल कर दी। क्लाइव ने मिरर को बताया कि लोगों को लग रहा था कि सजा हमें अलग कर देगी मगर इसने हमें एक दूसरे के ओर नजदीक ला दिया। हम 24 घंटे एक दूसरे के बारे में सोचने लगे। यह एक जादू था। ब्रेंडा ने बताया कि क्लाइव एक भद्रपुरुष है। वह मेरी देखभाल करता है। क्लाइव की पूर्व पत्नी और ब्रेंडा की बेटी इरेन को लगता है कि उसे उसकी मां ने धोखा दिया। कि कौन मेरी मां है।

उसका कहना है कि मैं नहीं जानना चाहती कि कौन मेरी मां है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने क्लाइव और ब्रेंडा का मामला उठाया। इसके बाद मामले पर सात यूरोपीय जजों की पीठ ने विचार किया और फैसला दिया कि अनुच्छेद 12 को हटा दिया जाए जो इस जोड़े को शादी का अधिकार देने से रोकता है।

भारत ने चीन की डिजिटल जासूसी के खिलाफ उठाया सख्त कदम, एक्सपर्ट कमेटी से 30 दिन में मांगी रिपोर्ट

इंटरनेशनल डेस्क।

भारत के खिलाफ चीन की साजिशों की पोल खुलती जा रही है और भारत द्वारा ड्रैगन के खिलाफ कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। स्ट पर करारे जवाब के बाद अब चीन द्वारा भारत में करीब 10,000 लोगों के डाटा की निगरानी करने के मामले की बारीकी से जांच के लिए भारत सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में भारत सरकार ने डिजिटल जासूसी की इन रिपोर्टों का अध्ययन करने, उनका मूल्यांकन करने और कानून के किसी भी उल्लंघन का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के तहत एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है यह कमेटी 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मालूम हो कि चीन की शेनजेन स्थित इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी जेन्हु पर लगभग 10 हजार भारतीय नागरिकों पर 'डिजिटल जासूसी' का गंभीर आरोप लगा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को सरकार के इस फैसले की जानकारी भी दी है, क्योंकि उन्होंने और कई सांसदों ने सरकार से अपील की थी कि चीन की जासूसी से भारतीय राजनेताओं और दूसरे लोगों के डाटा को बचाया जाए। सूत्रों के अनुसार विदेश मंत्रालय ने चीन की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी जेन्हु पर लगे कथित डिजिटल जासूसी के आरोपों का मुद्दा भारत में चीन के राजदूत के सामने भी उठाया। चीन ने कहा कि जेन्हु एक निजी कंपनी है और सार्वजनिक रूप से अपने बारे में बता चुकी है। सूत्रों ने आगे बताया कि भारत सरकार इस रिपोर्ट को बहुत गंभीरता से ले रही है, जिसमें बताया गया कि विदेशी बिना हमारी सहमति के हमारे नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा तक पहुंचने या प्राप्त करने की कोशिश कर रह हैं। भारतीय नागरिकों की गोपनीयता और निजी डेटा की सुरक्षा को भारत सरकार बहुत गंभीरता से लेती है। मालूम हो कि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि चीन भारत में करीब 10,000 लोगों के डाटा की निगरानी कर रहा है। चीन भारत के हाई प्रोफाइल लोगों पर भी नजर बनाए हुए है जिसमें पीएम मोदी से लेकर सोनिया गांधी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीजेआइ एसए बोबडे, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जैसी टॉप हस्तियां चीन की निगरानी में है। कंपनी इन हस्तियों की रियल टाइम निगरानी कर रही है. इसमें उनसे जुड़ी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सूचना शामिल है। इस लिस्ट में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, महाराष्ट्रके सीएम उद्धव ठाकरे, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक का नाम भी शामिल है।

10,000 भारतीय लोगों की जासूसी कर रहा चीन। जासूसी करने वाली चीनी कंपनी का कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध ।

ट्रंप ने अवैध ड्रग्ज उत्पादकों की सूची में भारत सहित 20 देशों को किया चिह्नित

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और 20 अन्य देशों को अवैध मादक पदार्थों के बड़े उत्पादक देशों के तौर पर चिह्नित किया है। ट्रंप ने इन्हें मादक पदार्थों का पारगमन करने वाले देश भी बताया है। ट्रंप ने साथ ही इस बात पर जोर दिया कि उनका प्रशासन मादक पदार्थों से जुड़े आपराधिक संगठनों और उनके समर्थकों से अभूतपूर्व पैमाने पर लड़ाई लड़ रहा है। ट्रंप ने साथ ही बोलीविया और वेनेजुएला में निकोलस मादुरो शासन के पिछले 12 महीनों के दौरान अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ निरोधक समझौतों के तहत अपने दायित्वों का पालन करने में स्पष्ट तौर पर विफल होने का भी उल्लेख किया। ट्रंप ने कहा, ''उल्लेखित सूची में किसी देश का शामिल होना, जरूरी नहीं कि उसकी सरकार के मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई या अमेरिका के साथ सहयोग के स्तर को प्रतिबिंबित करे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान, भारत, बहामास, बेलीस, बर्मा, कोलंबिया, कोस्टा रिका और डोमिनिकन गणराज्य आदि प्रमुख मादक पदार्थ पारगमन या अवैध मादक पदार्थ उत्पादन करने वाले देश हैं। ट्रंप ने आरोप लगाया कि इस गोलार्ध का सबसे बड़ा सरगना वेनेजुएला का तानाशाह निकोलस मादुरो है। उन्होंने कहा, ''कोलंबिया में राष्ट्रपति इवान ड्यूक और उनकी सरकार अमेरिका के मजबूत साझेदार हैं। कांलबियाई पुलिस और सैन्य बलों ने उच्च स्तर के मादक पदार्थ तस्करों को निशाना बनाकर और कोको का उन्मूलन करके बहुत बहादुरी और प्रतिबद्धता दिखायी है। ट्रंप ने कहा कि फिर भी, कोको की खेती और कोकीन का उत्पादन अस्वीकार्य रूप से उच्च स्तर पर बना हुआ है। ट्रंप ने इसको लेकर चिंता जतायी कि कोको की खेती और कोकीन का उत्पादन पेरू में ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर है ।

भारतीयों के लिए अमेरिका जाना हुआ और मुश्किल! एच-1बी वीजा पर रोक के खिलाफ दायर याचिका खारिज

इंटरनेशनल डेस्क।

भारतीय मूल के अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने 169 भारतीयों की अपील खारिज दी जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा इस साल के अंत तक एच-1बी वीजा के आधार पर आने वाले विदेशियों के देश में प्रवेश करने पर लगाई गई अस्थायी रोक को चुनौती दी गई थी। एच-1बी वीजा गैर-आव्रजन वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को सैद्धांतिक एवं प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता वाले पदों पर विदेशी कामगारों को नियुक्त करने की सुविधा देता है। प्रौद्योगिकी कंपनिया हर साल भारत और चीन जैसे देशों के हजारों कामगारों की नियुक्ति पर निर्भर हैं। कोलंबिया जिले की संघीय अदालत के जिला न्यायाधीश अमित पी मेहता ने बुधवार को दिए आदेश में कहा कि भारतीय नागरिक जो सीमा बंद होने के बाद भारत में फंस गए हैं, उनका मुकदमा जीतना असंभव है जिसमें ट्रम्प द्वारा लगाए गए यात्रा प्रतिबंध को चुनौती दी गई है। मेहता ने कहा कि 169 भारतीय नागरिकों ने अपने मुदकमे में विदेश मंत्री और अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को डीएस-160 वीजा आवेदन पर प्रक्रिया करने, निस्तारण करने और अंतिम फैसला करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है लेकिन यह प्रक्रिया तब बेकार साबित होगी जब शिकायतकर्ता एक जनवरी 2021 तक देश में प्रवेश करने से अयोग्य हैं।

न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे किसी आदेश से सीमित संसाधन की अर्हता रखने वाले लोगों के आवदेन की प्रक्रिया से दूसरी ओर मुड़ने का खतरा होगा जिन्हें राष्ट्रपति की घोषणा से छूट दी गई है और इससे वीजा प्राप्तकर्ताओं के बीच भ्रम का माहौल पैदा होगा जो देश में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे और जिन्हें हवाई अड्डे पर प्रवेश देने से इनकार ही किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह मुकदमा उन भारतीयों ने दायर किया था जो हाल तक अमेरिका में कानूनी तौर पर गैर-आव्रजक दर्जे के साथ अस्थायी कामगार के तौर पर रहे थे और जिनको अमेरिकी आंतरिक मंत्रालय ने मंजूरी थी। हालांकि, जिनको अमेरिकी आंतरिक मंत्रालय ने मंजूरी थी। हालांकि, वे विभिन्न कारणों से भारत गए और अब अमेरिका आने के लिए उन्हें वीजा की जरूरत है।

संक्षिप्त समाचार

कोरोना के बाद दुनिया को फिर डरा रहा चीन, 3,000 लोग पाए गए ब्रुसेलोसिस पॉजिटिव

इंटरनेशनल डेस्क। कोरोना संकट से मच रही भारी तबाही के के बीच चीन से आई खबर ने दुनिया को एक बार फिर से डरा दिया है। उत्तर-पश्चिम चीन में 3000 से ज्यादा लोग ब्रुसेलोसिस पॉज़िटिव पाए गए हैं। हालांकि अब तक इस वायरस से कोई ख़तरा पैदा नहीं हुआ है। खबरों की मानें तो पिछले साल एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी में लीक के बाद कई हजारों लोग ब्रुसेलोसिस पॉज़िटिव पाए गए। हैं। गांसु प्रांत की राजधानी लान्चो के स्वास्थ्य आयोग के अनुसार फिलहाल 3,245 लोग ब्रुसेलोसिस से संक्रमित हैं। हालांकि ये वायरस ज्यादा खतरनाक नहीं है लेकिन चिकित्सकों का कहना है कि इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। ब्रुसेलोसिस बीमारी जीनस ब्रूसेला के बैक्टीरिया समूह से फैलती है, जो जानलेवा नहीं होती है। संक्रमित माता द्वारा ब्रेस्ट फीडिंग से शिशुओं में संक्रमण हो सकता है। चिकित्सकों के अनुसार पशुपालन और जानवरों के मांस का काम करते है, उनके ब्रुसेलोसिस संक्रमित होने की आशंका अधिक रहती है। मनुष्यों के लिए ब्रुसेलोसिस का टीका नहीं आया है। केवल पशुओं में ब्रुसेलोसिस से बचाव के लिए टीकाकरण किया जाता है।

आईएसआईएस से जुड़े पाकिस्तानी डॉक्टर का अमेरिका में होगा मनोवैज्ञानिक परीक्षण

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका की एक अदालत ने एक पाकिस्तानी डॉक्टर और मेयो क्लिनिक के पूर्व अनुसंधानकर्ता का मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने का आदेश दिया है। डॉक्टर पर आरोप है कि उसने के मुखबिरों को बताया था कि वह इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है और अमेरिका में 'लोन वुल्फ हमला करना चाहता है। मुहम्मद मसूद पर विदेशी आतंकी संगठन को सहायता मुहैया कराने का आरोप है। वह 19 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से मिनियापोलिस-सेंट पॉल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में है। संघीय मजिस्ट्रेट न्यायाधीश के आदेश के अनुसार मसूद पर मुकदमा चलने की स्थिति में वह अपना बचाव कर सकने में सक्षम है या नहीं यह जानने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाएगा। मसूद के वकील ने कहा कि प्रतिवादी अदालत की कार्यवाही नहीं समझ सकता। अभियोजन पक्ष का कहना है कि मसूद अमेरिका में काम करने के वीजा पर आया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार जनवरी से मार्च के बीच मसूद ने मुखबिरों को कई बार बताया कि वह इस्लामिक स्टेट से जुड़ा है। मसूद यह मानता था कि मुखबिर भी आतंकी संगठन से संबंध रखते हैं। अदालत के दस्तावेजों में उस क्लिनिक का नाम नहीं है जहां मसूद काम करता था।

नेपाल ने संदिग्ध गतिविधियों के लिए 41 चीनी पर्यटकों को किया निर्वासित

इंटरनेशनल डेस्क। नेपाल ने अपने दोस्त देश चीन के 41 पर्यटकों को निर्वासित कर दिया है। हालाँकि नेपाल आय के लिए पर्यटन पर निर्भर है लेकिन नेपाली सरकार ने 41 अंतरराष्ट्रीय मेहमानों को उनकी संदिग्ध गतिविधियों के लिए निर्वासित कर किया है। गृह मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार ये चीनी नागरिक पर्यटक वीजा पर नेपाल आए थे । उनकी गलती के लिए, उन्हें एक साल के लिए नेपाल में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आव्रजन विभाग के महानिदेशक रमेश कुमार केसी ने कहा है कि नेपाल में रहने के दौरान उनकी संदिग्ध गतिविधियों का पता चलने के बाद उन्हें हटा दिया गया है।हालांकि मेहमानों को सामान्य रूप से वापस भेजना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून के लिए यह अनिवार्य है। हालांकि मेहमानों को सामान्य रूप से वापस भेजना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून के लिए यह अनिवार्य है।

ट्रंप टिकटॉक मामले में सभी विकल्पों पर कर रहे विचार

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टिकटॉक पर व्हाइट हाउस के सभी विकल्पों की समीक्षा कर रहे हैं क्योंकि उनका प्रशासन चीनी वीडियो ऐप और अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल के बीच एक सौदे का मूल्यांकन कर रहा है। व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार लैरी कुदलोउ ने गुरुवार को इस आशय की जानकारी दी। उन्होंने कहा,''टिक्टॉक के बारे में राष्ट्रपति आज समीक्षा कर रहे हैं क्योंकि वह पिछले 72 घंटे से सभी विकल्प ... सबसे विशेष रूप से सुरक्षा और स्वामित्व पर विचार कर रहे हैं। इसलिए, हमें समय बीतने के साथ और अधिक जानकारी होगी।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

शहीद का राष्ट्रिय सम्मान के साथ अन्तिम संस्कार

'शहीद को देख आंखें हुई नम'

कानपुर(घाटमपुर)विकास खंड भीतरगांव के गांव चिलहटा निवासी शहीद अमोल सिंह का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव पहुंचा शहीद को देख उपस्थित जन सैनाब की आंखें नम हो गई। चीन बार्डर पर तैनात चिलहटा निवासी नायब सूबेदार अमोल सिंह दो दिन पूर्व सिक्किम के यादरी बार्डर में गस्त के दौरान बर्फ में पैर फिसलने से गहरे खड्ड में गिरने से गम्भीर घायल हो गया था। जिसे साथी फौजी तुरंत अस्पताल ले भागे जहां रास्ते में ही अमोल सिंह ने दम तोड दिया ।जिसकी सूचना साथी सैनिक हिम्मत सिंह ने परिजनों को दी।

आज शहीद का पार्थिव शरीर गाव पहुंचते ही कोहराम मच गया। शहीद के अंतिम दर्शन को पहुंचे जनप्रतिनिधियों राजाराम पाल, राकेश सचान,कमलरानी की पुत्री, अवनीश साहू ओमजी तिवारी सहित हजारों क्षेत्रीय ग्रामीणों की आंखें नम हो गई।

पुलिस ने अपनी छवि सुधारना शुरू किया

उन्नाव जनपद उन्नाव में कोविड –19 के दृष्टिगत चलाये जा रहे अभियान में 199 लोगो के विरूद्ध मास्क न लगाये जाने व थूकने के संबंध में कुल रूपये 99,500/– का चालान वसूला गया ।विभिन्न धाराओं में कुल 69 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिसमें आबकारी अधि ानियम व एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अभियोगो के अभियुक्त भी शामिल हैं ।थाना अजगैन पुलिस व स्वाट टीम की संयुक्त कार्यवाही में NDPS ACT के तहत दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनके कब्जे से 28.50 कि0ग्रा0 गांजा बरामद किया गया ।अवैध शराब निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 08 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर कुल 228 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद किये गये तथा लगभग पांच कुंटल लहन व एक भट्टी को नष्ट किया गया । दिनांक 18.09.2020 को यातायात नियमों के उल्लंघन के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए '

कुल 257 चालान किये गये तथा रुपये 16,900 शमन शुल्क वसूला गया।

सार–समाचार

जिम्मेदारो की लापरवाही से समुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य ठप

मंगतरबेडा उन्नाव,असोहा ब्लाक के गांव तूरी छविनाथ मजरे रायपुर में जिम्मेदारी की लापरवाही से एक माह से सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य ठप है। श्रमिक बेरोजगारी का दंश झेल रहे है। ब्लाक के ग्राम पंचायत तूरी छविनाथ मजरे रायपुर मैं 5.71 लाख लागत से 8 सीट का सामुदायिक शौचालय का निमाणॅ दो माह पहले शुरू कराया गया था। ग्राम प्रधान व सचिव की लापरवाही से निर्माण कार्य को रोक दिया गया था। निर्माण कार्य मे ग्राम पंचायत के दो दर्जन मनरेगा श्रमिको व ट्रेडर्स का भुगतान खींच तान के चलते नही हो सका। श्रमिक भुखमरी की कगार पर है। सूत्रों की माने तो ग्राम पंचायत में कराये जाने वाले विकास कार्यों का एक वर्ष से लंबित हें। जिम्मेदार एक दूसरे पर आरोप लगाकर पल्ला झाड रहे है। जबकि इसका दंश श्रमिकों सहित ट्रेडसॅ क्रो झेलना पड रहा है। ग्राम प्र ाान सुधीर शुक्ला का कहना है कि एक बर्ष से सचिव जगन्नाथ मिश्रा ने राज्य वित्त व चौदहवें वित्त मैं लेबर ब मटेरियल का भुगतान नहीं किया है। जिससे श्रमिक कार्य करने को तैयार नही है और ट्रेडर्स वालो के पास उधारी अधिक होने की वज़ह से फर्म मालिक मटेरियल देने को तैयार नही हे। सचिव जगन्नाथ मिश्रा ने बताया कि प्रधान सहयोग नही कर रहे हे। जिससे कार्य बाधित हो रहे हे।

पुत्र ने पिता की लाइसेंसी बन्दूक से खुद को गोली मारी।

सदर,उन्नाव दिव्यांश पुत्र श्रीकांत निवासी सिविल लाइन थाना कोतवाली जनपद उन्नाव द्वारा अपने घर में अपने पिता के लाइसेंसी रिवाल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली मृतक कक्षा 10 का छात्र था पिता ग्राम विकास अधिकारी सिकंदरपुर कर्ण में है परिजनों द्वारा घायल अवस्था में दिव्यांश को जिला अस्पताल लाया गया जहां पर डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया पोस्टमार्टम आज की कार्यवाही की जा रही है, बल्कि परिवार वालो का कहना है कि स्कूल वीरेन्द्र स्वरूप अकरमपुर के शिक्षकों ने फीस और और ऑनलाइन वर्क का डाला दबाव। पुलिस जांच में जुटी।।

दुकान की सफाई करते समय निकाल अजगर का बच्चा

सफीपुर,उन्नाव लोगों के बीच कोतवाल मच गया जब एक दुकान की सफाई करते समय अजगर का बच्चा निकल आया दुकानदार

दुकानदारों में भगदड़ मच गई तथा ग्रामीण ों में अधिकारों को देखने की होड़ लग गई दुकानदारों व ग्रामीणों में भय है अगर अजगर का बच्चा निकला है तो अजगर भी आस–पास में ही होगा।

उन्नाव डी एम ने किया बिछिया अस्पताल का दौरा।

बिछिया,उन्नाव वैसे तो देश मे करोना के केस दिन दुगनी और रात चौगुनी तेजी से बढ रहे है।उसी क्रम मे प्रदेश सरकार हो या जिला प्रशासन अपनी तैयारियों का निरीक्षण करती नजर आ रही है।उसी क्रम उन्नाव डी एम रवीन्द्र कुमार ने बिछिया एल–1 अस्पताल का निरीक्षण किया तथा डाक्टरों से वर्तमान स्थिति पर बातचीत की।

राष्ट्रीय पोषण माह अन्तर्गत अब तक 18 अतिकुपोषित परिवारों को किया गया गोदान

बहराइच। जिला कार्यक्रम अधिकारी जी.डी. यादव ने बताया कि जनपद में संचालित राष्ट्रीय पोषण माह अन्तर्गत मा. मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश आश्रम योजना के तहत प्रत्येक विकास खण्ड के 02–02 अतिकुपोषित बच्चों के इच्छुक अभिभावकों को 01–01 गाय तथा उसके भरण पोषण हेतु रू. 900/प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। श्री यादव ने बताया कि उक्त योजना के तहत अब तक 09 विकास खण्डों के 02–02 अतिकुपोषित परिवारों के अभिभावकों को गाय उपलब्ध करायी जा चुकी है।

डीपीओ श्री यादव ने बताया कि विकास खण्ड हुजूरपुर अन्तर्गत ग्राम भाटीकुण्डा की रागिनी के पिता विद्याराम व ग्राम रत्तापुर के दीपक के माता पिता लाखा देवी पत्नी त्रिभुवन तथा विकास खण्ड जरवल अन्तर्गत ग्राम महुरीकलॉ की आकृति की माता

ग्रीन जोन में परिवर्तित हुए 05 कन्टेनमेन्ट जोन

बहराइच । तहसील व थाना पयागपुर के ग्राम हलधरपुरवा लखाही पुतलीतारा, तहसील सदर के थाना रिसिया के ग्राम भोलें शहीद व सिसई सलोन, तहसील व थाना कैसरगंज के ग्राम कोनारी तथा तहसील महसी के थाना हरदी के ग्राम मुरेहरा में कोविड–19 के पीड़ित/संक्रमित व्यक्ति पाये जाने के फलस्वरूप घोषित किये गये हाट स्पाट/कन्टेनमेन्ट जोन को मुख्य चिकित्साधिकारी बहराइच की संस्तुति के आधार पर शासन के प्राविधानानुसार 14 दिनों से इस क्षेत्र में कोई पाजिटिव कोविड–19 मरीज की पुष्टि न होने के कारण जिलाधिकारी ने हाट स्पाट/कन्टेनमेन्ट जोन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है।

क्लीनिक के अंदर ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या

जौनपुर (एजेंसी)। जिले में सरपतहां क्षेत्र के अमारी गांव में गुरुवार रात ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

रात नौ बजे बाइक से आए बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दो हत्यारोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

जानकारी के मुताबिक सरपत. हा थाना क्षेत्र के अमारी गांव निवासी 47 वर्षीय बंसलाल बिंद प्रधान थे। वह झोलाछाप डाक्टर भी थे। गुरुवार रात वह अपनी डिस्पेंसरी में बैठे थे।

रात नौ बजे बाइक से आए दो बदमाशों ने उन्हें को लक्ष्य कर गोली मारी।

गोली लगते ही वह जमीन पर गिर पड़े।

आस–पास के लोग जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाते तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

छात्र नेता की गोली मारकर हत्या

लखीमपुर–खीरी (एजेंसी)। जिले के गोला कस्बे में गुरुवार की देर रात लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता की गोली मार के हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप छात्र नेता के करीबी रिश्तेदार पर ही लगा है। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता और भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े अमन बाजपेई (25) पुत्र विजय बाजपेई इन दिनों अपने घर गोला कस्बे में थे। बताया जाता है कि गुरुवार की देर रात उनका परिवार के लोगों से ही झगड़ा हो गया। इस दौरान मारपीट में अमन के एक करीबी रिश्तेदार ने उन्हें गोली मार दी गोली पेट और छाती के बीच जा लगी।

जख्मी हालत में परिजन उनको लेकर गोला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल से ही पुलिस को इस घटना की सूचना मिली। पुलिस ने अमन का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

किशोरी ने दर्ज कराया बलात्कार का मामला

बांदा (एजेंसी)। जिले के तिंदवारी थाना क्षेत्र में एक सत्रह साल की लड़की ने गांव के युवक के खिलाफ बलात्कार करने और ग्राम प्रधान पर धमकाने का मामला दर्ज कराया है। जानकारी के मुता. बिक बुधवार को गांव की 17 साल की लड़की की मां की तहरीर पर उसी गांव के युवक दिलशाद (19) के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। जबकि इसी घटना का उलाहना देने पर ग्राम प्रधान तथा दो अन्य के खिलाफ मारपीट, धमकाने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में घटना 12 सितंबर की बताई गयी है। घटना के वक्त लड़की शौच करने के बाद अपने घर वापस लौट रही थी, तभी 19 वर्षीय युवक दिलशाद ने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने लड़की का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया है, जिसमें बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है। लड़की के परिजन ने आरोपी युवक को बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया था, जिसका किसी निजी अस्पताल इलाज चल रहा है इसीलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। घटना की जांच की जा रही है।

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए विदेशों से भी चंदा ले सकेगा ट्रस्ट

अयोध्या(एजेंसी)। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए विदेश में रहने वाले लाखों रामभक्तों से भी चंदा लिया जा सकेगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कार्यालय में विदेशों से चंदा देने के लिए रोजाना आ रहे फोन के मद्देनजर अब गृह मंत्रालय से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए) के तहत इजाजत लेने के लिए आवेदन किया है। अनुमति मिलते ही लाखों की तादाद में विदेशों में रह रहे भारतीय भी राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दे सकेंगे। अयोध्या में भूमिपूजन के बाद से चंदा देने वाले लोग चेक, मनीऑर्डर, ऑनलाइन ट्रांसफर, नकदी समेत आभूषण,

गृह मंत्रालय से एफसीआरए के तहत इजाजत लेने के लिए आवेदन किया

चांदी की ईंटें आदि के जरिये चंदा भेज रहे हैं। ट्रस्ट के सूत्रों के अनुसार, राम मंदिर के लिए 70 करोड़ रुपये से ज्यादा का चंदा श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अकाउंट में जमा हो चुका है। सबसे ज्यादा चंदा ट्रस्ट के एसबीआई खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर के द्वारा आया है। राममंदिर ट्रस्ट के कार्यालय में भी रोजाना करीब 20 से 30 हजार की नकदी आ रही है। इसके अलावा प्रतिदिन कई चेक भी आ रहे हैं, जिन्हें ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में जमा कराया जाता है। इसके अलावा मनीऑर्डर भी बड़ी संख्या में डाकखाने में आ रहे हैं। ट्रस्ट एनआरआई से चंदा हासिल करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक में एक एनआरआई अकाउंट भी खुलवाने जा रहा है। क़ानून के तहत भारत में जब कोई व्यक्ति या संस्था, एनजीओ किसी विदेश व्यक्ति से चंदा लेती है तो उसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए) यानी विदेशी सहयोग विनियमन अधिनियम के नियमों का पालन करना होता है।

सरकारी बस में सवारी बैठाने पर प्राइवेट बस संचालक के गुर्गों ने सरकारी बस स्टॉप के साथ गाली गलौज कर की मारपीट तथा दी धमकी

तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ किया मामला दर्ज

ललितपुर(एजेंसी)पिछले कई दिनों से सरकारी बस सेवा के स्टाफ और प्राइवेट बस स्टॉप में काफी खींचतान चल रही है । और उसका सबसे बड़ा कारण है कि प्राइवेट बस संचालक अपने पाले हुए गुर्गों के बल पर सरकारी बस स्टॉप को तरह–तरह की ध मकियां देते हैं । उनके साथ गाली गलौज कर मारपीट करते हैं और बस में सवारी न बैठाने का दबाव बनाते हैं जिससे वह अपनी बस में सवारियों को बैठाकर मनमाना किराया वसूल कर सकें । हालांकि प्राइवेट बस संचालकों की मनमानी से आने जाने वाले यात्री ही काफी परेशान है । इसी तरह की घटना एक बार फिर सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बस स्टैंड के नजदीक अभिलाषा पेट्रोल पंप के पास घटी है। जिसमें प्राइवेट बस संचालक और उनके दबंग गुर्गों द्वारा सरकारी बस संचालक द्व ारा सवारी बैठाने पर उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट की गई तथा उन्हें तरह–तरह की धमकियां भी दी गई। घटना के संबंध में पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी बस संचालक और उनके गुर्गों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभिलाषा पेट्रोल पंप के पास सरकारी बस संचालक नरेंद्र सिंह पुत्र नारायण सिंह निवासी थाना सौजना स्थानीय कस्बे ने सदर कोतवाली पुलिस को लिखित रूप से एक शिकायती पत्र दिया । जिसमें अवगत कराया कि नॉन स्टॉप वैजयंती बस मडावरा के संचालक महेंद्र सिंह निवासी ग्राम रमेशरा अपने तीन अज्ञात साथियों के साथ उसकी सरकारी बस पर आए और सवारी बैठाने को लेकर विवाद करने लगे। जिससे सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हुई इसके साथ ही सरकारी बस चालक से सवारी ना बैठाने की धमकी देते हुए कहा कि यदि उसने सवारी बैठाई तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे । इसके साथ ही सभी ने एक राय होकर उसके साथ जमकर गाली–गलौज की और जब उसने उन लोगों की इस गाली गलौज का विरोध किया तो सभी लोगों ने उसके साथ जमकर मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी भी दी । सदर कोतवाली पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर तहरीर के आधार पर सभी दबंग आरोपियों के खिलाफ 323 504 353 332 धाराओं में मामला पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। इस मामले में अब देखना होगा कि जब प्राइवेट दबंग बस संचालक और उनके गुर्गों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया । तो अब क्या सरकारी बस संचालकों और स्टाफ का उत्पीड़न रुकता है या फिर दादागिरी यूं ही बरकरार रहती है।

मजदूरों से भरी वैन बोरिंग मशीन से टकराई, चालक समेत तीन की मौत

चंदौसी (एजेंसी)। शुक्रवार सुबह हुए एक हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि तीन लोग बुरी तरह घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक चंदौसी जिले के गांव रसूलपुर कैली के पास शुक्रवार सुबह मुरादाबाद हाईवे पर एक ईको वैन बोरिंग मशीन से टकरा गई। हादसे के बाद वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वैन के अंदर बैठे छह लोग बुरी रह घायल हो गए। सभी को वैन के बाहर से निकाला गया। इलाज के लिए सभी को अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बरेली जिले के आंवला थाना क्षेत्र के गुरनपुर गांव के रहने वाले धनीराम (45), बदायूं जिले के मूसाझाग थाना क्षेत्र के रुखड़ा गांव निवासी धीरेन्द्र सिंह (25) और वैन चालक प्रवीण (35) जो कि पानीपत शहर के मानक का निवासी को मृतक घोषित कर दिया। हादसे में पीली. भीत जिले के गजरौला थाना क्षेत्र के घिपेना निवासी प्रदीप कुमार, बदायूं जिले के उघैती थाना क्षेत्र के गोदी नगला गांव के राजेश कुमार, उसका चचेरे भाई राजू को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया है। बताया जाता है कि मृतकों में दो लोग कंबल बेचने का काम करते थे। तीसरा मरने वाला व्यक्ति वैन चालक है। हादसे में अन्य तीन लोग भी घायल हुए हैं वह भी पानीपत में कंबल बेचने का काम करते थे।

162-बांगरमऊ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन-202 की तैयारियों के लिये बैठक

उन्नाव, जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट में 162–बांगरमऊ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन–202 की तैयारियों को लेकर नामित प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक की गई।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि कोविड प्रोटोकाल के कारण सभी की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं।

निर्वाचन से सम्बन्धित सभी विषयों पर तैयारी कर ली जाये। एक्शनप्लान तैयार करलें ताकि निर्वाचन से जुड़ समस्त कार्यों को सुगमता से किया जा सके। उन्होंने उप जिलाधिकारी बा. गरमऊ को निर्देश दिये कि क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन पर बैठक कर स्थिति का जायजा ले लें।

इस दौरान जिलाधिकारी ने पेड न्यूज, जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण समिति, (एमसीएमसी), क्रिटिकल/वल्नरेबिल पोलिंग स्टेशन, मतदान कार्मिक, मतगणना कार्मिक, माइक्रो प्रेक्षक, सहायक व्यय प्रेक्षक की व्यवस्था, मतदान/मतगणना कार्मिकों, माइक्रोप्रेक्षकों, सहायक व्यय प्रेक्षकों का प्रशिक्षण पर चर्चा करते हुये कहा कि कोविड–19 को देखते हुये प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। उन्होंने स्वीप प्लान, नामांकन व्यवस्था, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट प्लान, शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था, शिकायत एवं आदर्श आचार संहिता, भारी/हल्के वाहन ईंधन व्यवस्था, मतदान पार्टी प्रस्थान तथा वापसी व्यवस्था, मतदान व्यवस्था, प्रेक्षक व्यवस्था, ई0वी0एम0 स्ट्रांग रूम तैयार करना, मतदान पार्टी प्रस्थान स्थल, मतगणना स्थल का साइट प्लान तैयार करना,

समाधान, सुगम, सुविधा एवं आई0वी0डी0एस0, मतपत्र व्यवस्था, टेंट फर्नीचर बैरिकेडिंग एवं विद्युत व्यवस्था, लेखन सामग्री और निर्वाचन सामग्री की व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं वीवीपैट व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन/ वीवीपैट की प्राप्ति तथा उन्हें मतदान हेतु तैयार किए जाने का व्यवस्था, मतदान सूची की व्यवस्था, सांख्यकीय सूचनाओं के प्रेषण की व्यवस्था,

मतगणना के पश्चात् ईवीएम की सुरक्षा, निर्वाचन व्यय लेखा व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, कंट्रोल रूम की व्यवस्था, कंप्यूटराइजेशन एवं एस0एम0एस0 मॉनिटरिंग, वीडियोग्राफी, कम्युनिकेशन प्लान, मानचित्र एवं सेक्टर/ जोन का गठन, वेबकास्टिंग (सीसीटीवी) सीसी कैमरा, सेवा नियोजित मतदाता तथा निर्वाचन ड्यूटी वाले कार्मिकों को पोस्टल मतपत्र जारी किए जाने की व्यवस्था,

मीडिया कम्युनिकेशन, निर्वाचन संबंधी सूचनाओं का संकलन एवं उनका प्रेषण तथा बुकलेट तैयार करना, दिव्यांग मतदाताओं के लिए सुविधाएं प्रदान करना आदि विषय पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

यूपी में कोरोना के 6494 नए मामले, अब तक 4869 की मौत

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 6494 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोविड–19 के कारण राज्य में अब तक कुल 4869 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले 24 घण्टे में 98 लोगों की मौत हुई है। सूबे में सक्रिय मामलों की संख्या भी बढ़कर अब 68 हजार के करीब पहुंच गई है।

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने शुक्रवार को यहां बताया कि 6494 नए मामलों के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या अब तीन लाख 42 हजार 788 हो गई है। इनमें से दो लाख 70 हजार 094 लोग इलाज के बाद पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 78.79 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की चपेट में आकर बीते 24 घंटे में 98 लोगों की मौत हुई है और मौत का आंकड़ा अब 4869 हो गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में फिलहाल कोरोना के 67 हजार 825 संक्रिय मामले हैं। इनमें से 35 हजार 124 लोग होम आइसोलेशन में हैं। वहीं प्राइवेट अस्पतालों में कुल 3926 लोग हैं। इसके अलावा सेमी पेड अस्पताल में 202 लोग अपना कोरोना का इलाज करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक कुल एक लाख 73 हजार 782 लोगों ने होम आइसोलेशन का विकल्प चुना और इनमें से एक लाख 38 हजार 782 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि गुरुवार को राज्य में कुल एक लाख 55 हजार 897 कोरोना सैंपल्स की जांच हुई। अब तक कुल 82 लाख 85 हजार 710 कोरोना नमूनों की उत्तर प्रदेश में जांच हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हम पिछले कुछ दिनों से प्रतिदिन डेढ़ लाख या इसके आसपास टेस्ट कर रहे हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट, सीबीनैट, ट्रूनैट और आरटीपीसीआर माध्यम से टेस्टिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में अभी तक 64 हजार 505 कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जा चुकी है। इसके माध्यम से कुल सात लाख 57 हजार 435 लक्षणात्मक लोगों की पहचान की गई है।

क्रांति समय

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

अधिकारी महेरबान,बिल्डर का विकास, जनता परेशान

एक छोटे से बांधकाम में अधिकारी नोटिस के कर अपना फर्ज पूरा करते हैं तो इस बांधकाम में क्या अधिकारी अपना फर्ज भूल गई की किसी और मैजिक का कमाल हैं नई सामेल हुए अनेक क्षेत्रों में अधिकारीयों की महेरबानी से चल रहा यह सारा करोबार?

दिल्ली के बस्तियो मे जबरन बेदखली के खिलाफ सूरत में मेरा घर

मेरा अधिकार अभियान द्वारा मौनिक विरोध के साथ सोपा गया ज्ञापन

सूरत : दिल्ली के फरीदाबाद एरिया में कई सालो से लोग रह रहे थे। कुछ दिनों पहले देश की सर्वोच्च न्यायलय द्वारा दिल्ली के फरीदाबाद में कुल 100 एकड़ में फैले हुवे लगभग 48 हजार मकानों को तोड़ने का आदेश दिया गया है। तभी संबंधित प्रशासन द्वारा तुरंत उस जगह पोहचकर 48 हजार मकानों को तोडा जाने लगा था। परंतु तब यह थोडा भी नहीं सोचा गया की इस वैश्विक कोरोना महामारी के वक्त ईन 48 हजार मकानों को तोड़ने के बाद वह गरीब, श्रमिक और बेसहारा लोगोको क्या तखलिफे झेलनी पड़ेगी? उनकी क्या परिस्थिति होगी? उनके छोटे बच्चे एवं वयो वृद्ध लोग इस स्थिति में कहा जायेंगे? अगर उनको हटाया भी जा रहा हो तो उनके सकारात्मक पुनर्वास के लिए सरकार ने कितने हद तक काम किया है? ऐसी कोई भी तैयारी के बिना स्थानीय प्रशासन द्वारा वहा बेदखली कर कई नुकशान किया गया था।

इस सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुवे आज तारीख : 18 सितम्बर 2020 को सूरत शहेर में ''मेरा घर मेरा अधिकार अभियान'' द्वारा दिल्ली में बस्तियो मे जबरन बेदखली के खिलाफ जिल्ला कले.

क्टरको ज्ञापण देकर मौनिक विरोध प्रदर्शन किया गया था। साथ ही हमारे प्रतिनिधि से बात करते हुवे इस अभियान के सदस्य श्री आदेश साबळे जी इन्होने बताया की उनके इस विषय ओ लेकर कुछ सामान्य सी प्रमुख मांग है।

इस विषय को लेकर हमारी कुछ मुख्य मांग है, आशा है की वह आप जरुर स्वीकारेंगे :

1)रेलवे जमीन पर बसी वस. हतो के लिए ''भ्वनेपदह वित ।सस'' के संकल्प को लेकर एक कानून या रास्ट्रीय स्थर निति बनानी चाहिए 2)जबरन बेदखली पर रोख लगाकर, ''जब तक पुनर्वास नही तब तक डिमोलेशन नही'' यह लागु करना चाहिए

3) कोई भी विस्तृत योजना बनाने में बस्तीमे रहने वाले लोगोका पूरा योगदान और भागीदारी को और उनकी रजामंदी के बिना कोई आयोजन तै न किया जाये 4)कोई भी योजना केन्द्रीय और राज्य सरकारों के जहा वसाहत वहा मकान के वादे के अनुसार स्थानीय विकास को प्राथमिकता देना चाहिए 5)पुनर्वास को पुनस्थापित तभी किया जाये जब और कोई रास्ता शेष न हो और जब लोग पुर्नवास को लेने के लिए संपूर्णतः सहमती प्रदान करते है 6)पुर्नवास तभी हो जब सामाजिक और सपूर्ण मुलभुत सेवाए पूरी तरह से तैयार हो और यातायात के और किफायती संसाधनों का नियोजन भी किया जाना चाहिए 7) आर्थिक अक्षमता के कारण कोई परिवार पुनर्वास से वर्जित न हो 8)DUSIB 2015 निति के अनुसार कोई भी पुनर्वास 5 किमी से अधिक दुरी पर न हो 9) रेलवे तंत्र यह सु. निच्चित आशवासन करे की चार सप्ताह के बाद भी संपूर्ण प्रक्रिया पूरी होने तक जबरन बेदखली ना होगी 10)रेलवे तंत्र यह सुनिच्चित आशवासन दे की कोविड जैसी वैश्विक महामारी के दौरान कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी

निजी स्कूलों में फीस पर राज्य सरकार स्वयं फैसला करे : हाईकोर्ट

अहमदाबाद राज्य में निजी स्कूलों द्वारा वसूली जा रही मन. मानी फीस को लेकर गुजरात हा. ईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए सरकार को स्वतंत्र फैसला करने

का आदेश दिया हैद्य हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के पास विशाल सत्ता है और जिसका उसे उपयोग करना चाहिएद्य दरअसल लॉकडाउन के चलते मार्च महीने से स्कूलें बंद हैं,

जिसकी वजह से अभिभावक स्कूलों में अपने बच्चों की फीस जमा नहीं करा रहेद्य जबकि निजी स्कूल संचालकों के नित नए हथकंडे अपनाकर अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैंद्य इस संदर्भ में राज्य सरकार की ओर से कई दफा मध्यस्थता किए जाने के बावजूद कोई समाधान नहीं होने पर मामला गुजरात हाईकोर्ट पहुंच गया।

हाईकोर्ट ने आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार के पास विशाल सत्ता हैं। इसके बावजूद सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लियाद्य हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि वह अपनी सत्ता का उपयोग करते हुए निष्पक्ष फैसला कर अधिसूचना जारी करे इस मुद्दे पर सरकार स्वयं फैसला करने के बजाए हाईकोर्ट को मध्यस्थी बनाना चाहती है। लेकिन हाईकोर्ट को क्यों मध्यस्थता करनी चाहिएद्य सरकार स्वयं फैसला करे और उसका अमल करे।

हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए शिक्षा मंत्री भूपेन्द्रसिंह चूड़ास्मा ने कहा है कि राज्य में स्कूलों की फीस के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले की कॉपी राज्य सरकार को मिलने के बाद वे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिनभाई पटेल के साथ इस फैसले के संदर्भ में बैठक करेंगे।

उन्होंने कहा कि इस बैठक में चर्चा एवं विचार करने के बाद राज्य सरकार इस मामले में योग्य निर्णय लेगी।

स्कूल फीस मामले को लेकर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के संदर्भ में मीडिया के साथ बातचीत में शिक्षा मंत्री ने यह जानकारी दी।

बुलेट ट्रेन परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 90 हजार से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की महात्वाकांक्षी एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के अमलीकरण कराने वाले नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन (एनएचएसआरसीएल) ने आज कहा कि इसके निर्माण के दौरान ही प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों मिलाकर 90 हज़ार से अधिक रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। कारपोरेशन की प्रवक्ता सुषमा गौर ने आज जारी बयान में कहा कि निर्माण सम्बंधी काम के लिए 51000 से अधिक टेक्निशियन तथा कुशल और अकुशल कामगारों की ज़रूरत होगी। कारपोरेशन ऐसे लोगों को विभिन्न सम्बंधित कामों के लिए प्रशिक्षण देने की सम्भावनाएं तलाश रहा है। पटरी बिछाने के लिए कारपोरेशन ठेकेदारों के कर्मियों के विशेष प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करेगा। उन्होंने बताया कि निर्माण के दौरान 34000 से अधिक अप्रत्यक्ष

रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे।

480 किमी से अधिक लम्बी इस पटरी में 460 किमी लम्बा वायाडक्ट (ज़मीन के ऊपर बनी पुलनुमा संरचना) और समुद्र के नीचे 7 किमी समेत कुल 26 किमी लम्बी सुरंगें, 27 लोहे के पुल, 12 स्टेशन और कई अन्य सहायक सुपर संरचनायें होंगी। इसके निर्माण के दौरान 75 लाख टन सीमेंट, 21 लाख टन स्टील का इस्तेमाल होने का अनुमान है। इससे भी सम्बंधित उद्योगों और उनसे जुड़ी आपूर्ति श्रंखला में रोज़गार के अतिरिक्त अवसर पैदा होंगे।

2016 में गठित इस कारपोरेशन की प्रवक्ता ने बताया कि निर्माण सम्बंधी कुछ महत्वपूर्ण कामों के लिए निविदाएं अगले दो माह में खुलेंगी और उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा। इस परियोजना के लिए अब तक कुल ज़रूरत की 64 प्रतिशत भूमि अधिग्रहीत हो चुकी है जिसमें से 82 प्रतिशत गुजरात और केंद्र शासित क्षेत्र दादरा और नगर हवेली में तथा क़रीब 23 प्रतिशत महाराष्ट्र में है।

बताते चलें कि जापान की सहायता वाली इस परियोजना के कार्य का औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापानी समकक्ष शिंजो आबे की मौजूदगी में सितंबर 2017 में अहमदाबाद में किया था।

गुजरात में कोरोना की रफ्तार तेज, 1410 नए केस, 1293 ठीक हुए, 16 मौतें

अहमदाबाद गुजरात में सितंबर की शुरुआत से रोजोना कोरोना के 1300 से अधिक मामले आ रहे थे और आज यह आंकड़ा 1400 को पार कर गया है। राज्य में पहली बार 1410 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जबकि 1293 लोग ठीक हुए हैं और 16 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। राज्य में कोरोना के कुल केसों की संख्या 1.20 लाख को पार कर गई हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटों में सूरत कॉर्पोरेशन में 176, अहमदाबाद कॉर्पोरेशन में 152, सूरत में 110, जामनगर कॉर्पोरेशन में 104, राजकोट कॉर्पोरेशन में 98, वडोदरा कॉर्पोरेशन में 94, बनासकांठा में 48, मेहसाणा में 47, राजकोट में 46, वडोदरा में 41, कच्छ में 34, मोरबी में 30, पंचमहल में 28, पाटन में 27, अमरेली में 26, भरुच में 26, गांधीनगर में 25, जामनगर में 25, गांधीनगर कॉर्पोरेशन में 23, अहमदाबाद में 21, जूनागढ़ कॉर्पोरेशन में 21, भावनगर कॉर्पोरेशन में 20, भावनगर में 16, दाहोद में 16, जूनागढ़ में 16, साबरकांठा में 16, गिर सोमनाथ में 14, सुरेन्द्रनगर में 13, खेडा में 12, आणंद में 11, महीसागर में 11, बोटाद में 10, नर्मदा में 9, देवभूमि द्वारका में 8, अरवल्ली में 7, पोरबंदर में 7, छोटाउदेपुर में 6, नवसारी में 5, तापी में 5, वलसाड में 4 और डांग में 2 समेत राज्यभर में कुल 1410 कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज हुए और 1293 लोगों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गयां। इस दौरान अहमदाबाद कॉर्पोरेशन में 3, राजकोट कॉर्पोरेशन में 3, सूरत में 3, वडोदरा कॉर्पोरेशन में 2, गांधीनगर में 2, गांधीनगर कॉर्पोरेशन, राजकोट, सूरत कॉर्पोरेशन और वडोदरा में 1–1 समेत कुल 16 मरीजों की पिछले 24 घंटों में कोरोना से मौत हो गईं । स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक आज 69077 समेत राज्यभर में अब तक कुल 3678350 लोगों का टेस्ट किया जा चुका है और इसमें कुल 120498 कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज हुए। जिसमें से 101101 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो गए हैं। जबकि 3289 मरीजों की कोरोना से मौत हो गईं । शेष 16108 एक्टिव केसों में 16010 की हालत स्टेबल और 98 मरीज वेन्टीलेटर पर हैंद्य राज्य के विभिन्न जिलों में आज की तारीख में 605373 लोगों को कोरन्टाइन किया गया है। 604914 होम कोरन्टाइन और 459 लोगों को फैसिलिटी कोरोन्टाइन में रखा गया है।

बाल तस्करी का पर्दाफाश, एनजीओ और सीआईडी क्राइम ने 32 बच्चों को बचाया

अहमदाबाद शहर के कालूपुर रेलवे स्टेशन पर सीआईडी क्राइम ब्रांच और एनजीओ ने 32 बच्चों को गुजरात में अलग अलग जगहों पर बाल मजदूरी के लिए भेजने से पहले बचा लिया।

इन बच्चों को बिहार से निज. ामाबाद एक्सप्रेस से अहमदाबाद लाया गया था।

अहमदाबाद के अलावा वडोदरा, रतलाम और कोटा से भी 18 बच्चों को मुक्त कराया गया है। लॉकडाउन और कोरोना के कारण मजदूर नहीं मिल रहे। इस समस्या से निपटने के लिए नाबालिग बच्चों को अहमदाबाद लाया जा रहा होने की जानकारी एनजीओ और

सीआईडी क्राइम ब्रांच को मिली थी।

सूचना के आधार पर सीआईडी क्राइम एनजीओ के साथ अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन पर वॉच पर थी। उसवक्त बिहार से आई निजामाबाद एक्सप्रेस में 15 से 17 वर्षीय आयु के 32 बच्चे मिलेद्य इन सभी बच्चों को बाल मजदूरी के लिए भेजने से पहले ही पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया।

जानकारी के मुताबिक कालूपुर रेलवे स्टेशन रेस्क्यू किए गए च्चोंको राजकोट और जेतपुर में मजदूरी के लिए भेजा जाना थाद्य अहमदाबाद के अलावा वडोदरा से 7, राजस्थान के कोटा से 9 और मध्य प्रदेश के 3 नाबालिगों बच्चों को पुलिस ने मुक्त कराया होने की जानकारी है।

अगस्त में ली गई कक्षा 10 की पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित

अहमदाबाद गुजरात माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अगस्त 2020 में ली गई कक्षा 10 की पूरक परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए। 25 से 28 अगस्त के दौरान ली गई पूरक परीक्षा का परिणाम 8.17 प्रतिशत आया है। जिसमें फिर एक बार छात्राओं ने बाजी मार ली है। लड़कियों का परिणाम 8.36 प्रतिशत और 8.04 प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए हैं।

परिणाम में दिव्यांगों को 20 प्रतिशत पासिंग का लाभ दिया गया है और ऐसे 245 विद्यार्थी पास हुए हैं। कक्षा 10 के कुल पंजीकृत 132032 में 108869 विद्यार्थियों परीक्षा दी थी। जिसमें 64801 छात्रा और 44068 छात्र शामिल हैं। 108869 मं8 केवल 5207 छात्राएं और 3683 समेत कुल 8890 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को मार्कशीट और प्रमाण पत्र और मार्च 2020 की परीक्षा में पास हुए विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र का वितरण 21 सितंबर से किया जाएगा। विद्यार्थियों की मार्कशीट और प्रमाण पत्र 18 सितंबर को जिला स्तर पर पहुंचाए जाएंगे और जिलास्तर से कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए तहसीलवार, स्कूल विकास परिसर या कॉर्पोरेशन क्षेत्रों में जिला कचहरी पर वितरण की व्यवस्था की जाएगीं। परिणाम के पुनर्जांच के इच्छुक विद्यार्थियों को बोर्ड की वेबसाइट www.gseb.org पर दी गई सूचनाओं का अध्ययन कर जरूरी फीस भरनी होगी और उसके बाद 7 दिन में रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए आवेदन करना होगा। कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए आवेदन प्रत्यक्ष स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

क्रांति समय
स्पेशल ऑफर
अपने बिज़नेस को बढ़ाये हमारे साथ
ADVERTISEMENT WITH US
सिर्फ 1000/- रु में
(1 महीने के लिए)
संपर्क करे

गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशूभाई पटेल कोरोना संक्रमित

अहमदाबाद गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता केशूभाई पटेल को कोरोना हो गया है। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद केशूभाई होम कोरन्टाइन हो गए हैं और गांधीनगर स्थित उनके निवास पर ही उनका उपचार चल रहा है। जानकारी के मुताबिक केशूभाई पटेल की केयर टेकर शीतल पंड्या की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। जिसके बाद केशूभाई पटेल का तुरंत टेस्ट किया गया और उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वह होम कोरन्टाइन हो गए हैं।

मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बताया कि केशूभाई पटेल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उनकी तबियत अच्छी हैद्य उन्होंने कहा कि केशूभाई पटेल के पुत्र भरत पटेल के साथ टेलीफोनिक बातचीत हुई है और केशूभाई पटेल के उपचार के लिए जरूरी आदेश दे दिए गए हैं।

उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने भी स्वास्थ्य विभाग को केशूभाई पटेल की तबियत पर ध्यान रखने का आदेश दिया है।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशक : सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास , (भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक :सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/751000 (Subject to Surat jurisdiction)